

केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने मां कर्मा के विशेष आवरण का अनावरण किया

डाक विभाग केवल पत्रवाहक नहीं,विरासत और संस्कृति के संदेशवाहक है - तोखन साहू

बिलासपुर । बिलासपुर में आयोजित जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी ‘बिलासापेक्स-2025’ के भव्य उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तथा बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि डाक टिकट केवल कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और महान विरासत का प्रतीक है। ये टिकटें हमें हमारे राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास और त्यागमयी परंपरा से जोड़ती हैं।

मंत्री साहू ने भक्त माता कर्मा जी पर आधारित विशेष आवरण का विमोचन करते हुए कहा कि यह केवल एक डाक आवरण नहीं, बल्कि करुणा, समानता और भक्ति की जीवंत गाथा है। माता कर्मा जी ने उस युग में सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए मानवता और प्रेम का संदेश दिया। जब भगवान जगन्नाथ ने स्वयं माता कर्मा द्वारा अर्पित खिचड़ी को



स्वीकार किया, वह सामाजिक एकता और समानता की विजय थी।

उन्होंने कहा कि डाक विभाग ने इस विशेष आवरण के माध्यम से एक ऐतिहासिक कार्य किया है उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि वे केवल पत्रवाहक नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और समरसता के सच्चे संदेशवाहक हैं। जब यह आवरण

देशभर में पहुँचेगा, तो मां कर्मा की भक्ति, मातृशक्ति और गौरव को महक को फैलाएगा।

कार्यक्रम में साहू ने सभी से यह आह्वान किया कि माता कर्मा जी की जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ा धर्म प्रेम है। आइए, हम सब मिलकर सामाजिक एकता, समानता और संस्कृति पर गर्व का संकल्प लें और अपने बिलासपुर को

नया रायपुर में सख्त सुरक्षा व्यवस्था : आयोजन स्थल में जाने वाले होते रहे परेशान

एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को पुराना माना बस्ती से होकर जाना पड़ा

मीडियाकर्मियों को कवरेज को लेकर हुई अनेक परेशानियां

रायपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन पर आज राजधानीवासियों और नया रायपुर तथा इससे लगे ग्रामीण क्षेत्रों, मीडियाकर्मियों तथा बाहर से आए विधायक एवं पूर्व कार्यकर्ताओं को विधानसभा सहित अन्य स्थानों में जाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा।

सत्यसाई अस्पताल में बच्चों से मिले प्रधानमंत्री

नया रायपुर अटलनगर में सुरक्षा के कारण सभी प्रमुख मार्ग आज बंद कर दिए गए थे। प्रधानमंत्री आज अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आए। वे एयरपोर्ट से सीधे सत्यसाई अस्पताल चले गए, इसके चलते राजधानी की

देश का विकास के मंत्र पर चलते हम भारत को विकसित बनाने के अभियान में जुटे

विश्व शांति की अवधारणा भारत के मौलिक

रायपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आने वाले समय में ब्रह्मकुमारीज विश्व शांति के प्रयासों का प्रमुख केन्द्र होगा। उन्होंने नया रायपुर शांति शिखर आडिटोरियम में कहा कि अध्यात्म, विश्वशांति, पर्यावरण, संस्कृति से जुड़े अनुभवों को भी साझा किया।

आज नया रायपुर के कयाबांधा के सेक्टर 20 में प्रजापिता ब्रम्हकुमारीज संस्थान में शांति शिखर एकेडमी फॉर वर्ल्ड स्ट्रीट सेंटर को समाज के नाम समर्पित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ध्यान लगाया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष तथा संस्थान की मुख्य प्रशासिका राज्य योगिनी दीदी एवं महासचिव राजयोगी मृत्युंजय भाई उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र ने इस अवसर पर



संबोधित करते हुए कहा कि हमेशा अनुभव किया है, ब्रह्माकुमारी संस्थान में शब्द कम और सेवा ज्यादा है। मैं शांति शिखर की संकल्पना में दादी जानकी जी के विचारों को साकार होते हुए देख रहा हूं। राज्य के विकास से देश का विकास के मंत्र पर चलते हुए हम भारत को विकसित बनाने के अभियान में जुटे हैं। विकसित भारत की इस अहम यात्रा में ब्रह्माकुमारीजु जैसी संस्था की अहम भूमिका है। मैंने इस आध्यात्मिक आंदोलन को वटवृक्ष की तरह विशाल होते देखा है।

को सशक्त करने में ब्रह्माकुमारी जैसे संस्थाओं की अहम भूमिका है।ब्रह्माकुमारीजु से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं बीते कई दशकों से आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं यहां अतिथि नहीं हूं मैं आपका ही हूं। इस संस्थान से मेरा अपनापन है। खासकर जानकी दीदी का स्नेह, राजयोगिनी दादी हृदयमोहिनी जी का मार्गदर्शन यह मेरी जीवन की विशेष स्मृतियों का हिस्सा है। मैं बहुत भाग्यवान रहा हूं। वर्ष 2011 में अहमदाबाद में प्यूचर ऑफपावर कार्यक्रम होे, वर्ष 2012 में संस्था की स्थापना के 75 वर्ष होे या वर्ष 2013 में प्रयागराज के कार्यक्रम होे, आबू जाना होे या गुजरात में किसी कार्यक्रम में जाना होे यह तो बहुत रूटीन सा होे गया था। दिल्ली आने के बाद भी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा अभियान होे, स्वच्छ भारत अभियान या जल जन अभियान इन सबसे जुड़ने का मौका होे, मैं जब भी आपके बीच आया हूं।

स्वर्ग की तरह दमक उठेगा नारायणपुर और केदार का धाम नारायणपुर

शहर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 6.98 करोड़ की गौरव पथ परियोजना को मंजूरी

जगदलपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और बस्तर की माटी के लाल वन मंत्री केदार कश्यप की पहल पर बस्तर संभाग के गांव और शहर तेजी से विकास कर रहे हैं और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो रहे हैं।नक्सल समस्या के विनाश के साथ ही संभाग में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। इसी कड़ी में नारायण के पुर यानि नगर और केदार के धाम नारायणपुर को भी सजाने संवारने की बड़ी पहल हुई है। इसके लिए राज्य शासन के करीब सात करोड़ रुपयों की मंजूरी दी है। व्यक्ति जिस माटी में जन्म लेता है, वह माटी उस व्यक्ति के

लिए चारों धाम के सामान होती है, क्योंकि उस धरती पर उसके माता पिता के भी चरण रज मिले होते हैं। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन एवं सहाकरिता मंत्री केदार कश्यप भी इसी नारायणपुर क्षेत्र की पावन माटी में पैदा हुए हैं और नारायणपुर क्षेत्र से ही विधायक चुने गए हैं।नारायणपुर उनके लिए तोर्थधाम के तुल्य है। अपनी माटी की सेवा करने में मंत्री केदार कश्यप हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में नारायणपुर नगर के विकास और सौंदर्यीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए शासन ने 6 करोड़ 98 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से पंकज वैरायटी चौक से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक आधुनिक सड़क गौरव पथ का निर्माण होगा की। यह गौरव पथ परियोजना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री

अरुण साव तथा छत्तीसगढ़ शासन में केबिनेट मंत्री एवं नारायणपुर के विधायक केदार कश्यप के प्रयासों से संभव हो पाई है।इस बड़ी सौगात पर वन मंत्री केदार कश्यप बोले- विकास और सुंदरता की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा- यह गौरव पथ नारायणपुर नगर की नई पहचान बनेगा। यह केवल सड़क नहीं, बल्कि शहर के विकास, यातायात व्यवस्था और सौंदर्यीकरण का प्रतीक होगा। हमारी सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है और यह परियोजना उसीजनकल्याणकारी सोच का प्रत्यक्ष उदाहरण है। श्री कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बस्तर अंचल के हर नगर को मूलभूत सुविधाओं से सशक्त किया जाए।

अपनी कर्मठता और दृढ़ इच्छाशक्ति से लौह पुरुष बने सरदार पटेल : मुख्यमंत्री साय

राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री: स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का किया सम्मान

सभी संभागीय मुख्यालयों में स्थापित की जाएगी सरदार पटेल की मय्य प्रतिमा

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ‘रन फॉर यूनिटी’ सहित विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन

रायपुर । देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल अपनी कर्मठता और दृढ़ इच्छाशक्ति से लौहपुरुष बने। आजादी के बाद के कठिन हालातों में उन्होंने अपनी सूझबूझ और फैलादी इरादों से 562 रियासतों का भारत में विलय कर अखंड भारत का निर्माण किया। किसानों के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अमूल्य रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर

आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में यह बात कही। यह कार्यक्रम खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रायपुर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया।इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब तथा विधायक राजेश मृणत उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर उनके महान योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने अपनी विराट सोच और अटूट इच्छाशक्ति से टुकड़ों में बंटी रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया। सरदार पटेल का जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और समर्पण का प्रतीक है। उनकी 150वीं जयंती पर आज पूरे देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गुजरात के केवडिया में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य को भी आमंत्रित किया गया है, जहाँ राज्य का विशेष स्टॉल भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि 'रन फॉर यूनिटी' केवल देश की एकता और अखंडता का प्रतीक नहीं



है, बल्कि यह पिछेसे और सामूहिक ऊर्जा का भी संदेश देता है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की आजादी और किसानों के अधिकारों के लिए ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध कठोर संघर्ष किया। उनके योगदान को रेखांकित करने के लिए ही उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा को साकार

किया।उप मुख्यमंत्री साव ने घोषणा की कि राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में सरदार पटेल की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संबंधित नगरीय निकायों को 50-50 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शाल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए रंगोली और चित्रों का अवलोकन किया तथा उपस्थित जनों को स्वदेशी अपनाने और भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग की शपथ दिलाई।राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रन फॉर यूनिटी के साथ ही महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए रंगोली, चित्रकला, भाषण एवं काव्य पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।मुख्यमंत्री श्री साय ने रंगोली, चित्रकला, भाषण और काव्य पाठ प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया तथा रन फॉर यूनिटी के प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 'बस्तर ओलंपिक' के प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाई।

पर एक वातानुलित संयंत्र बनाया गया है।

विंग-सी (मंत्रीगण कक्ष) विंग-सी के अपर ग्राउण्ड फ्लोर में मंत्रीगण के लिए 24 कक्ष, 2 समिति कक्ष एवं 1 केबिनेट हॉल स्थित है। लोवर ग्राउण्ड फ्लोर में एल्युपैथक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बैंक, पोस्ट आफिस, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, कैन्टीन आदि के लिए भी कक्षों का निर्माण किया गया है। मंच पर राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी जयंती दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी डॉ. मृत्युंजय भाई भी मौजूद रहे। ओम शांति के सम्बोधन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपने स्वयं को ही नहीं बल्कि विश्व और ब्रह्मांड को शांति के प्रयासों से जोड़ा है।

नया विधानसभा गर्भगृह को सिलिंग को कटोरे का स्वरूप दिया गया है

51 एकड़ में भूभाग में निर्मित है नया विधानसभा भवन

500 व्यक्तियों की क्षमता वाला आडिटोरियम

रायपुर । नया राज्य बनने के पश्चात भविष्य की क्षमता को देखते हुए 200 से अधिक विधायकों के बैठने का समायोजन किया गया है। वर्तमान सदस्यों की संख्या 90 है। विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा के तीन हैं। जिनमें सचिवालय सभाकक्षा, विंग बी सदन में 200 विधायकों की बैठने की क्षमता है। जिसमें नेता प्रतिपक्ष एवं कार्यालय स्थित है, जहां 220 व्यक्तियों क्षमता वाला दर्शकदीर्घा एवं 100 व्यक्तियों की क्षमता वाला मीडियादीर्घा बनाया गया है। यहां

आदिवासी पालकों ने स्कूल के सभी बच्चों के लिये अंग्रेजी डिक्शनरी की व्यवस्था की

धमतरी। आदिवासी अंचल में स्थित माध्यमिक शाला सेजेस सिंगपुर के आदिवासी पालकों ने स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के लिए अंग्रेजी डिक्शनरी की व्यवस्था की है। पालक चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी अंग्रेजी का ज्ञान हो। आज चहुँ ओर अंग्रेजी का बोलबाला है। इस स्थिति में बच्चों को अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर शिक्षकों के प्रस्ताव को पालकों ने स्वीकार कर अपने बच्चों के लिये अंग्रेजी डिक्शनरी की व्यवस्था की है। अब विद्यालय में इस डिक्शनरी का नियमित उपयोग होे रहा है। बच्चे प्रतिदिन नए नए शब्दों को लिखकर लाते हैं। प्रार्थना तथा कक्षा में सीखे हुए नए नए शब्दों का उच्चारण एवम अर्थ सभी के समक्ष रखते हैं। विद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन करने वाले योगेश साहू ने कहा है कि डिक्शनरी के आ जाने से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि हो रही है। शब्द भंडार के बाद बच्चों को स्पोकन इंग्लिश भी सिखाया जाएगा। इधर सेजेस सिंगपुर के प्राचार्य एवम सभी शिक्षकों ने पालकों के पहल की सराहना की है।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर कलेक्टर रोहित व्यास ने दिलाई एकता व अखंडता की शपथ

जशपुरनगर । देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्टर रोहित व्यास ने जिला कार्यालय परिसर में समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में अधिकारियों-कर्मचारियों ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए स्वयं को समर्पित करने तथा देशवासियों के बीच एकता का संदेश फैलाने की शपथ ली। इस दौरान अधिकारी-कर्मचारियों ने अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी व निष्ठा से योगदान देने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर प्रशांत कुशवाहा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन मिशन मीठी क्रांति का आगमन : बेहतर भारत का संकेत

पीआईबी

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी एनबीएचएम एक केंद्र प्रायोजित योजना है।इसे भारत सरकार ने देश में मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देकर गुणवत्ता परक शहद और मधुमक्खी उत्पादन के अन्य उत्पादों को प्रोत्साहित करना था। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित यह योजना आत्मनिर्भर भारत के बैनर पर 500 करोड़ की लागत पर चलाई जा रही है। वर्ष 2020-21 से शुरू इस योजना को पहले तीन साल के लिए लाया गया पर पूरा बजट नहीं खर्चने की वजह से इसकी मियाद तीन साल और बढ़ा दी गयी।

मधुमक्खी पालन एक कृषि जनित गतिविधि है जो आम तौर पर गांवों में किसानों और भूमिहीन श्रमिकों की समन्वित कृषि गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कई पौधों में परागन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जिस्मे फसल उत्पादन और किसानो की आमदनी बढ़ाने में सहायता मिलती है। इस कार्य से कई मूल्य वर्धित मधुमक्खी उत्पाद जिसमे मोम, मधु मक्खी पराग कण, प्रोपोलिस नामक पौधे, रॉयल जेली, बी वेनम इत्यादि के उत्पादन के जरिये किसानों की आजीविका के श्रोत और आमदनी बढ़ती है।

समन्वित खेती और सघन कृषि एक सामान्य और व्यापक शब्द है जिसके जरिया मौजूदा पारम्परिक तरीके की एक फसली खेती के बजाये एक बहुम्सली व समन्वित खेती को अंजाम दिया जाता है। इसका मतलब एक ऐसी कृषि प्रणाली से है जिसमे पशुपालन , मछली उत्पादन, अनाज उत्पादन और बागवानी कृषि सभी समाहित है।

भारत की विभिन्नताओं से भरी कृषि जलवायु परिस्थितियों में मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन और इसके निर्यात की व्यापक क्षमता है। ग्रामीण विकास और सतत कृषि में इसके महत्त्व को समझ कर ही भारत सरकार ने एक नयी मीठी क्रांति अभियान के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय मधुमक्खी शहद मिशन की शुरुआत की। यह एक महत्वाकांक्षी पहल है जिससे देश में गुणवत्तापरक शहद के उत्पादन के साथ किसानों की आमदनी वैज्ञानिक और संगठित तरीके से मधुपालन के जरिये बढे।

राष्ट्रीय मधुमक्खी शहद मिशन की उप योजनाएं
राष्ट्रीय मधुमक्खी शहद मिशन यानी एनबीएचएम का क्रियान्यवन तीन मिनी मिशन एमएम 1 एमएम 2 और एमएम 3



मिनी मिशन 1- इसके अंतर्गत वैज्ञानिक मधु पालन के तहत परागन क्रिया के जरिये विभिन्न फसलों का उत्पादन और उसकी उत्पादकता उन्नयन पर जोर दिया जाता है।

मिनी मिशन 2- यह मिशन मधुमक्खी पालन से जुड़े उत्पादों के आगम के उपरांत के प्रबंधन कार्य मसलन शहद संग्रहण, प्रसंस्करण, भण्डारण, विपणन और मूल्य वर्धन के लिए सभी जरूरी बुनियादी सुविधाओं को मुहैया करता है।

मिनी मिशन 3-यह मिशन देश के सभी क्षेत्रो के कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल तरह तरह के शोध व विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

एनबीएचएम का उद्देश्य एनबीएचएम का मुख्य उद्देश्य है किसानो की आमदनी और रोजगार की बढ़ोत्तरी के लिए मधुमक्खी

पालन उद्योग का संपूर्ण विकास, खेतिहर और गैर खेतिहर परिवारों को आजीविका मुहैया करना और खेती व बागवानी के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।

अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर मधुमक्खियों का एक क्वालिटी न्यूक्लियस स्टॉक बनाना है, फिर इस स्टॉक को कई गुना और बढ़ाकर शहद निकालने के उपरांत की गतिविधियों मसलन शहद प्रसंस्करण प्लांट, भंडारण, शीतायन, संग्रहण, ब्रांडिंग और विपणन की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है।

इसके अलावा शहद उत्पादन वाले जिलों और प्रान्तों में सभी तरह के आधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित करना जिससे सभी शहद उत्पादों की शुद्धता की जांच हो।

तुलसी विवाह एवं छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया



राजनांदगांव। आज तुलसी विवाह एवं छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर सिन्हा परिवार द्वारा विधिविधान से तुलसी विवाह की पूजा-अर्चना की गई। पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार तुलसी माता का श्रृंगार किया गया और भगवान शालिग्राम से उनका विवाह संपन्न कराया गया।

पूजा-अर्चना के पश्चात छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपरा और गौरवशाली इतिहास को याद किया गया। परिवार के सदस्यों ने एक-दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं और प्रदेश की खुशहाली व उन्नति

की कामना की।

इस अवसर पर घरों की सुंदर साज-सज्जा की गई तथा पूरे परिसर को दूधिया रोशनी से नहलाया गया, जिससे वातावरण अत्यंत भव्य और आध्यात्मिक बना रहा। सिन्हा परिवार ने बताया कि तुलसी विवाह और छत्तीसगढ़ दिवस दोनों पर्व एक साथ आने से इस वर्ष का आयोजन विशेष और यादगार बन गया।इस अवसर पर अंगेश्वर सिन्हा ,खुमेशवरी सिन्हा सृष्टि सिन्हा, विवेक सिन्हा, टुकेन्द्र सिंहा, हेमलता सिन्हा,अनुराग सिन्हा,अंजलि सिन्हा, भुनेश्वरी सिन्हा सहित सभी ने देव उठनी पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित किया।

राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम (केरल) में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) में सुगमता पर आठवीं क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया

पीआईबी

नीति आयोग द्वारा 30-31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस), तिरुवनंतपुरम में “‘अनुसंधान और विकास में सुगमता” पर 8वीं क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। परामर्श में भारत के अनुसंधान और विकास इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने और विचार-विमर्श करने के लिए संस्थागत नेताओं, कुलपतियों और वैज्ञानिक मंत्रालय/विभागों का एक प्रतिष्ठित समूह एक साथ आया।

एनसीईएसएस के निदेशक प्रो. एनवी चलपति राव के स्वागत भाषण से सत्र की शुरुआत हुई, जिन्होंने वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए एक अनुकूल वातावरण के महत्व को रेखांकित किया और नवाचार-आधारित विकास को गति देने में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डाला। नीति आयोग के प्रो. विवेक कुमार सिंह ने बैठक के बारे में जानकारी दी और नीति आयोग की अनुसंधान एवं विकास सुगमता पहल के मार्गदर्शक दृष्टिकोण के रूप में आरओपीई प्रेमवर्क - बाधाओं को दूर



करना, सक्षमताओं को बढ़ावा देना ड़्क पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि इस प्रेमवर्क का उद्देश्य शोधकर्ताओं के सामने आने वाली संस्थागत और नीति-स्तरीय चुनौतियों को रेखांकित करना और साथ ही वैज्ञानिक प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु आसान, अंतर-एजेंसी सहयोग और क्षमता विकास जैसे सहायक तकनीकी को बढ़ावा देना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव, डॉ. एम. रविचंद्रन ने अनुसंधान की दक्षता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए

ठोस सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने सेवानिवृत्त वैज्ञानिक प्रतिभा के अनुभव का उपयोग करने, विश्वविद्यालय-उद्योग-सरकार (यूआईजी) इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने, संस्थानों के बीच डेटा साझाकरण को बढ़ावा देना तथा वैज्ञानिक संचार को बेहतर बनाकर अनुसंधान परिणामों को समाज के लिए अधिक प्रासंगिक और समझने योग्य बनाने पर बल दिया। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर डाला कि अनुसंधान एवं विकास में

दो आसान महत्वपूर्ण तत्वों, आंतरिक और बाह्य कारकों पर निर्भर करती है। जहां आंतरिक कारक अनुसंधान संस्थानों की संरचना, प्रशासन और कार्यप्रणाली से संबंधित हैं, वहीं बाह्य कारक नियामक बाधाओं, वित्तपोषण तंत्र और विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय जैसे तत्वों को शामिल करते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अनुसंधान और नवाचार में वैश्विक अग्रणी बनने के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए दोनों आयामों पर एक साथ ध्यान देना जरूरी है।

इस बैठक में केरल के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर भी उपस्थित थे, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि “‘अनुसंधान एवं विकास में सुगमता” नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के व्यापक लक्ष्य से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जन-केंद्रित विकास के साथ जोड़ा जाना चाहिए, और संस्थानों, उद्योगों और सरकारों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण समावेशी विकास की कुंजी है।

भारत अनादि काल से ज्ञान की भूमि रही है : उपराष्ट्रपति

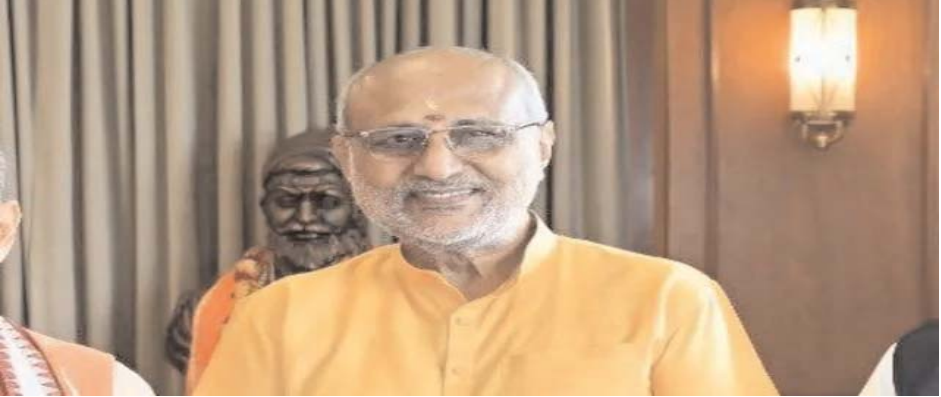
पुस्तकालय भारत के शिक्षा और ज्ञान के शाश्वत सभ्यतागत लोकाचार को प्रतिबिंबित करते हैं : उपराष्ट्रपति

डिजिटल युग में, गलत सूचनाओं के बीच पुस्तकालय विश्वसनीय मार्गदर्शक हैं: उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति ने डिजिटल साक्षरता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने में पुस्तकालयों की भूमिका पर जोर दिया

केरल के 80 वर्षीय पुस्तकालय आंदोलन और पी.एन. पणिक्कर फंडेशन के दृष्टिकोण की प्रशंसा की

पीआईबी। भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने आज एक वीडियो संदेश के माध्यम से तिरुवनंतपुरम के कनकक्कुतु पैलेस में पी.एन. पणिक्कर फंडेशन द्वारा आयोजित +पुस्तकालय समुदायों को सशक्त बनाते हैं - वैश्विक परिप्रेक्ष्य+ विषय पर



अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। यह आयोजन केरल में संगठित पुस्तकालय आंदोलन के 80वें वर्ष का प्रतीक है, जो भारत के पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन के अग्रदूत माने जाने वाले श्री पी.एन. पणिक्कर के विजन से प्रेरित है।

उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में ज्ञान प्रसार के माध्यम से पठन संस्कृति, डिजिटल साक्षरता और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में निरंतर योगदान के लिए पी.एन. पणिक्कर फंडेशन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा

कि फंडेशन का आदर्श वाक्य ड़्क “‘वैचु वलारुका” (पढ़ो और बढ़ो) - समाज को ज्ञान और समावेश की दिशा में लगातार मार्गदर्शन करता रहता है।

श्री सी.पी.राधाकृष्णन ने पुस्तकालयों को शिक्षा के मंदिर के रूप में सराहा और उन्हें ऐसे स्थान के रूप में वर्णित किया जो महत्वपूर्ण सोच का पोषण करते हैं और व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाते हैं।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री आदि शंकराचार्य ने आध्यात्मिक चेतना जागृत करने और विविध विचारों

को एकीकृत करने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि अनगिनत अन्य ऋषियों और विचारकों ने अपने ज्ञान, करुणा और दूरदर्शिता से हमारी सभ्यता को समृद्ध किया है।

भारत की प्राचीन सभ्यतागत प्रकृति पर विचार करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की शिक्षा की परंपरा - महाकाव्यों से लेकर आधुनिक पुस्तकालयों तक - राष्ट्र को ज्ञान और सामाजिक प्रगति की खोज के लिए अग्रसर करती है।

श्री सी.पी.राधाकृष्णन ने इस बात पर भी जोर दिया कि आज के डिजिटल युग में, पुस्तकालय ज्ञान के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं जो लोगों को प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने और गलत सूचनाओं का विरोध करने में सक्षम बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तकनीक सूचना तक आसान पहुंच प्रदान करती है, वहीं पुस्तकालय समाज में गहराई, चिंतन और सार्थक संवाद को बढ़ावा देते हैं।

उपराष्ट्रपति ने शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में केरल की असाधारण विरासत की प्रशंसा की। उन्होंने श्री पी.एन. पणिक्कर को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी दूरदर्शिता ने पुस्तकालयों को जीवंत सामुदायिक केंद्रों में बदल दिया, जिससे पुस्तकें और शिक्षा प्रत्येक नागरिक के करीब पहुंचीं।

ओडिशा के भुवनेश्वर में हथकरघा एवं हस्तशिल्प 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ

विचार-विमर्श में आजीविका को मजबूत करने और विरासत को संरक्षित करने के लिए डिजाइन नवाचार, डिजिटल सशक्तिकरण और सहकारी संघवाद पर जोर दिया गया

पीआईबी

ओडिशा के भुवनेश्वर में आज हथकरघा एवं हस्तशिल्प 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें भारत के हस्तनिर्मित क्षेत्र को विकसित भारत 2047 के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में पुनः परिकल्पित करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालयों द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और क्षेत्र के विशेषज्ञ भारत के हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योगों के विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण तैयार करने हेतु



एक एकरत्र हुए। विचार-विमर्श दो प्रमुख उद्देश्यों पर केंद्रित रहा: हस्तनिर्मित अर्थव्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य का आकलन करना तथा आगामी राष्ट्रीय योजना

की रूपरेखा तैयार करना, जिसका उद्देश्य गहन राज्य भागीदारी, एकीकृत शासन और सतत क्षेत्रीय विकास है। वस्त्र मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम शमी राव ने

आज सम्मेलन के दूसरे दिन की अध्यक्षता की, जिसमें ओडिशा की अपर मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त श्रीमती अनु गर्ग और ओडिशा सरकार की आयुक्त-सह-सचिव (हथकरघा, वस्त्र एवं हस्तशिल्प) श्रीमती पूनम गुप्ता तपस कुमार भी उपस्थित थीं।

अपने संबोधन में, सचिव (वस्त्र) श्रीमती नीलम शमी राव ने उत्पादकता बढ़ाने और कठिन परिश्रम को कम करने के लिए पारंपरिक शिल्प कौशल को आधुनिक उपकरणों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सचिव ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) जैसे संस्थानों से बाजार चक्र से पहले डिजाइन और रंग के रद्धान के पूर्वानुमान में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। अंतर-राष्ट्रीय समन्वय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने हस्तशिल्प क्षेत्र में कुशल आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के बीच कच्चे माल की निर्बाध आवाजाही का आह्वान किया। अपने संबोधन का

समापन करते हुए उन्होंने कहा, हमें उसी इकोसिस्टम की रक्षा करनी चाहिए जिसे हम पोषित कर रहे हैं। चाहे हम इसे हथकरघा कहें या हस्तशिल्प, इसे हमारी अर्थव्यवस्था के एक गौण हिस्से के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए- यह वास्तव में भविष्य का प्रीमियम उत्पाद है। सचिव (वस्त्र) श्रीमती नीलम शमी राव ने यह भी कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच निरंतर संवाद सुनिश्चित करने, सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में परस्पर ज्ञान प्राप्त करने तथा हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए ऐसे सम्मेलन हर छह महीने में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने दोहराया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप एक मजबूत, समावेशी और नवाचार-संचालित हस्तनिर्मित अर्थव्यवस्था के साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए निरंतर समन्वय और आवधिक प्रशिक्षण आवश्यक है। श्रीमती अनु गर्ग ने हथकरघा के सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य को दोहराया तथा कोटपाड़ और डोंगरिया शॉल को टिकाऊ उदाहरण बताया।

संपादकीय

भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती गूगल का महा-निवेश

अमेरिका ने पेट्रोडॉलर समूद्ध पश्चिम एशियाई देशों के ऊर्जा एवं वित्त तथा भारत के टेक प्रशिक्षित मानव संसाधन को अपने एआई बौद्धिक संपदा से जोड़ कर इस नई तकनीक में खुद को अग्रणी बनाए रखने की बड़ी योजना बनाई है। गूगल भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब की स्थापना के लिए 15 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। इसके तहत विशाखापत्तनम में एक



मैं, तेरे ख्याल से शर्मा जाता हूँ।

परछाइयों में तेरी रंग मिलता हूँ, तेरे एहसासों के संग बहा जाता हूँ।

तेरा एहसास बड़ा इंद्रधनुषी जानम, तेरे ख्यालों में बीखर बिखर जाता हूँ

तेरे सांसों की खुशबू से इतर कोई महक नहीं सह पाता हूँ ।

जाने कितने गुलशनों में भटकता रहा, हसीन तुझसा फूल नहीं चुन पाता हूँ।

महकती आ जाओ कभी पहलू में, सारी रतियाँ आंखों में गुजार जाता हूँ।

तेरे तस्सवुर से भीगा अभी तक मैं, तेरे ख्याल से शर्मा जाता हूँ।

बंदीशें तो तुझ पर भी हैं बहुत पर मैं हवा में तेरे नाम पैगाम लिख जाता हूँ।

तू मिल जाए तो सारा जहाँ अपना , बिना तुम्हारे मैं तनहा रह जाता हूँ।

तेरे ख्याल से भीगी रातें नहीं कटती रातें करवटें बदलते रह जाता हूँ।

तेरा संग न होना एक सजा ही है, मुस्कुराकर ये सितम झेल जाता हूँ।

जब भी तेरा जिक्र होंगें पे आता है मधु सा मीठा गीत गुनगुना पाता हूँ।

हर सांस में अपने को खोजता संजीव तेरी हर परछाई में भी समा जाता हूँ।

संजीव ठाकुर



PM: 2024 -
Vishwa Sarkar Ka Vikalp



Modimaya
Vaidik Netritva



Rashtriya Ekta



DLF-Vadra-
Bhrasht Tantra



Silent Assassins
Jan11,1966



Accursed & Jihadi
Neighbour

सूखे नशे की गिरफ्त में दुनिया,भारत में नशे का आलम भयावह

संजीव ठाकुर, स्तंभकार,

महान साहित्यकार प्रेमचंद ने कहा था +युवक वही जो अपनी ऊर्जा समाज के निर्माण में लगाए, विनाश में नहीं।+ आज वही संदेश पुनः प्रासंगिक है। आज भारत एक ऐसे गंभीर दौर से गुजर रहा है जहाँ आर्थिक, तकनीकी और वैचारिक प्रगति के समानांतर एक सामाजिक महामारी जन्म ले रही है ड्रम्स की। नशे की यह घातक लत हमारे युवा वर्ग को धीरे-धीरे विनाश की ओर ढकेल रही है। यह केवल स्वास्थ्य या सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता और भविष्य की चेतना से जुड़ा संकट बन चुकी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (हृष्ट्रक्र) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में ड्रम्स से संबंधित अपराधों में पिछले पाँच वर्षों की तुलना में लगभग 37त की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, नशे के प्रभाव में किए गए बलात्कार, लूट, हत्या और हिंसक अपराधों की दर में भी लगातार वृद्धि देखी गई है। देश के महानगर-मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पंजाब, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई-इन अपराधों के सबसे बड़े केंद्र बन चुके हैं। मुंबई पुलिस की नारकोटिक्स इकाई ने केवल पिछले एक वर्ष में 12,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं, जिनमें कोकीन, चरस, अफीम, हेरोइन और एमडी ड्रम्स जैसी घातक वस्तुएं शामिल हैं। मुंबई, गोवा और गुजरात की समुद्री सीमाएं अब ड्रम्स तस्करी के प्रमुख मार्ग बन चुकी हैं, जहाँ पाकिस्तान और अफ्गानिस्तान से लेकर म्यांमार तक का नेटवर्क सक्रिय है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (हहृष्ट्रष्ट) की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया में ड्रम्स का लगभग 30त अवैध कारोबार भारत के रास्ते से होता है, जो न केवल हमारी युवा पीढ़ी के लिए खतरा है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्थिरता पर भी चोट करता है।

नशे का सबसे भयावह पहलू यह है कि यह व्यक्ति की चेतना, विवेक और संवेदना को नष्ट कर देता है। एक बार यह लत लगने पर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली बदल जाती है और व्यक्ति अपराध करने में हिचकिचाता नहीं। अपराधशास्त्री डॉ. अरविंद नायर के शब्दों में, +ड्रम्स व्यक्ति से मनुष्यत्व छीन लेता है, और जब इंसान की संवेदना मर जाती है, तब समाज में अपराध जन्म लेता है।+ यही कारण है कि नशे में धुत अपराधियों द्वारा किए गए बलात्कार, हत्या, लूट और सड़क दुर्घटनाएं समाज के लिए एक स्थायी भय बन चुकी हैं।

दूसरी ओर, कॉलेजों और स्कूलों में भी ड्रम्स ने अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दी हैं। किशोरों में 'ड्रैड ड्रम्स' यानी सूखे नशे (स्ख, स्ख, कोकीन पाउडर आदि) का चलन तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से इन पदार्थों की बिक्री अब 'डिजिटल अपराध' का नया रूप बन चुकी है। राष्ट्रीय युवा सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, भारत में 15 से 24 वर्ष की आयु के लगभग 12त युवा किसी न किसी रूप में नशे के संपर्क में हैं, और इनमें से 70त को यह आदत कॉलेज परिसर या मित्र मंडली से मिली। यह आँकड़ा न केवल चिंताजनक बल्कि आने वाले सामाजिक विघटन की चेतावनी भी है।

फिल्म उद्योग और ग्लैमर वर्ल्ड में भी ड्रम्स की पैठ ने समाज में एक खतरनाक आकर्षण पैदा किया है। सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण के दौरान सामने आए मादक पदार्थ नेटवर्क ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसने यह उजागर किया कि ड्रम्स की लत अब केवल समाज के निचले तबके तक सीमित नहीं, बल्कि उच्चवर्गीय समाज, कॉर्पोरेट पार्टियों, और आलीशान होटलों तक फैल चुकी है। वर्ष 2024 के नववर्ष की पूर्व संस्था पर केवल मुंबई और गोवा में लगभग 300 से अधिक ऐसी पार्टियों की पहचान पुलिस ने की, जहाँ सूखे नशे का सेवन किया जाना था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर इस विषय पर गहरी चिंता

जताई है। उन्होंने कहा कि +नशा समाज का नहीं, संकल्प का शत्रु है। इससे लड़ाई केवल कानून से नहीं, जनजागरूकता से जीती जाएगी।+ वास्तव में, केवल पुलिस कार्रवाई या कानूनी सख्ती पर्याप्त नहीं है। समाज को इस बुराई के विरुद्ध सामूहिक चेतना के रूप में उठना होगा। नशे के विरुद्ध विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को जागरूकता की निरंतर पहल करनी होगी।

ड्रम्स तस्करी अब एक अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध बन चुकी है। अफ़गानिस्तान के 'गोल्डन त्रीसैंट' और म्यांमार-थाईलैंड के 'गोल्डन ट्रायंगल' से होकर आने वाला मादक पदार्थों का नेटवर्क भारतीय सीमा तक फैला हुआ है। सीमा सुरक्षा बल (इक्स) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (हृष्ट्रक्र) लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु तस्कर अब डिजिटल मुद्रा, डार्क वेब और नकली व्यापारिक चैनलों के माध्यम से नये रास्ते बना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नशे की आपूर्ति श्रृंखला को नष्ट नहीं किया गया, तो इसका असर भारत की उत्पादक शक्ति-यानी युवाओं-पर स्थायी चोट के समान होगा।

नशे का दूसरा भयानक आयाम ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में शराब और सस्ती दवाओं का दुरुपयोग है। गरीब वर्ग में यह लत आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक विनाश का कारण बन रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 40त परिवार ऐसे हैं जहाँ नशे की वजह से घरेलू हिंसा और आर्थिक क्षति



ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों ही गठबंधनों ने बढ़-चढ़कर लोकलुभावनी और जनता को आकर्षित या गुमराह करने वाली घोषणाओं से जुड़े चुनावी घोषणा पत्र जारी किए हैं। इन घोषणा पत्रों में जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं, वे निश्चित रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। यह प्रश्न अब गंभीर हो गया है कि क्या घोषणा पत्र लोकतंत्र के महाकुंभ यानी चुनाव का सबसे सशक्त हथियार बन चुके हैं या चुनावी छलावा? निश्चित ही यह जनता को रिसाने और प्रभावित करने का प्रमुख माध्यम बन गया है, परंतु सत्ता में आने के बाद कितने राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों का अक्षरशः पालन किया है, यह बड़ा सवाल है। वास्तव में घोषणा पत्र किसी दल का दृष्टिपत्र होता है, जो उसके विचारों, उद्देश्यों और संकल्पों का सार्वजनिक दस्तावेज है। यह बताता है कि दल सत्ता में आने के बाद राज्य या देश की दिशा कैसी तय करना चाहता है, किन मूलभूत समस्याओं का समाधान करना चाहता है और विकास की कौन सी राह पर चलना चाहता है। घोषणा पत्रों में किए गए वादों को लेकर परस्पर विरोधी दलों में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तो छिड़ता है, लेकिन उन्हें लेकर वैसी सार्थक बहस नहीं हो पाती, जैसी विकसित देशों में होती है और जिसके आधार पर वहां स्वस्थ जनमत तैयार करने में मदद मिलती है। हैरानी नहीं कि अपने यहां चुनावी घोषणा पत्र अपनी महत्ता खोते जा रहे हैं।

लोकतंत्र में घोषणा पत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मतदाताओं के लिए जानकारी और निर्णय का आधार बनता है। मतदाता यह जान सकते हैं कि कौन-सा दल किस विषय पर क्या सोचता है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं और वह किन वर्गों के कल्याण के लिए क्या योजनाएं रखता है। यह राजनीतिक दलों की जनता के प्रति सार्वजनिक प्रतिज्ञा होती है, एक तरह की जवाबदेही का प्रतीक। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय लोकतंत्र में यह जवाबदेही सिर्फकागजों पर ही रह गई है। अधिकांश दल चुनाव जीतने के बाद घोषणा पत्रों को भूल जाते हैं। मतदाता भी अपने वोट के बदले वादों की पूर्ति का हिसाब नहीं मांगते। परिणामस्वरूप घोषणा पत्र एक औपचारिकता और दिखावे का माध्यम बनकर रह गए हैं। इतिहास पर नजर डालें तो अधिकांश घोषणाओं का पालन आधा-अधूरा ही हुआ है। राजस्थान में पिछली सरकार ने अपने घोषणा पत्र के लगभग 64 प्रतिशत वादे पूरे किए, जबकि कर्नाटक में सिर्फतीन प्रतिशत वादे ही पूरे हुए। यह आंकड़े बताते हैं कि घोषणा पत्र को गंभीरता से न तो दल लेते हैं, न जनता। यह स्थिति लोकतंत्र की आत्मा के विपरीत है, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि जनता अपने प्रतिनिधियों से सवाल करे और जवाब मांगे।

घोषणा पत्रों की एक बड़ी समस्या यह है कि उनमें की गई घोषणाएं वित्तीय दृष्टि से असंभव होती हैं। जनता को खुश करने के लिए ऐसे वादे किए जाते हैं जिनके लिए न तो संसाधन हैं, न कोई ठोस योजना। कोई कानूनी प्रावधान भी नहीं है कि दल अपने वादे पूरे न करने पर जवाबदेह बने। यही कारण है कि चुनाव के बाद घोषणाएं भुला दी जाती हैं। बिहार चुनाव के संदर्भ में देखें तो एनडीए और



महागठबंधन दोनों ने अत्यधिक आकर्षक और लोकलुभावन वादों से भरे घोषणा पत्र जारी किए हैं। एनडीए ने अपने 'संकल्प पत्र' में एक करोड़ नौकरियों का वादा किया है, महिलाओं को दो लाख रुपये तक की सहायता, हर जिले में कौशल केंद्र, किसानों के लिए नौ हजार रुपये वार्षिक सम्मान निधि और सात नए एक्सप्रेस-मार्गों के निर्माण की बात कही है। वहीं महागठबंधन ने अपने 'तेजस्वी प्रण' में प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी देने, महिलाओं को छई हजार रुपये मासिक सहायता, पच्चीस लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, दो सौ यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी और मंडियों की बहाली जैसे बड़े वादे किए हैं। दोनों घोषणाओं में एक बात समान है- वे अत्यधिक महत्वाकांक्षी और जन-लोभक हैं। नौकरियों, मुफ्त बिजली, नकद सहायता और भारी निवेश की घोषणाएं सुनने में तो आकर्षक लगती हैं, पर इनकी व्यावहारिकता संदिग्ध है। बिहार जैसे राज्य में, जहां संसाधन सीमित हैं और रोजगार की स्थिति जटिल है, इन वादों को लागू करना आसान नहीं है। घोषणाओं में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इतने बड़े खर्चों का वहन कैसे होगा, कौन-से विभाग या योजनाएं इनका संचालन करेंगे और कब तक परिणाम दिखेंगे।

इन घोषणा पत्रों में जनकल्याण की भावना अवश्य है, परंतु वह यथार्थ से अधिक कल्पना पर आधारित लगती है। बिहार की वास्तविक समस्याएं- शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवासी मजदूर, कृषि संकट, रोजगार और उद्योगों का अभाव, इनका समाधान केवल लोकलुभावन वादों से नहीं होगा। आवश्यक है कि दल घोषणाएं करने से पहले उनकी वित्तीय और प्रशासनिक व्यवहार्यता का गंभीर अध्ययन करें। राजनीति में घोषणा पत्रों का उपयोग अब एक चुनावी हथियार के रूप में हो रहा है, न कि जनसेवा की प्रतिबद्धता के रूप में। मतदाता को भी जागरूक होना होगा कि वे केवल वादों से प्रभावित न हों, बल्कि यह जानने की कोशिश करें कि पिछले चुनावों में किए गए वादों में से कौन-से पूरे हुए। मीडिया और सामाजिक संस्थाओं को भी यह दायित्व निभाना चाहिए कि वे चुनावों के बाद घोषणाओं की निगरानी करें, ताकि दल जवाबदेह बनें। घोषणा पत्र तभी सार्थक होंगे जब उनमें किए गए वादे मापनीय, समयबद्ध और संसाधन-सिद्ध हों। दलों को चाहिए कि वे घोषणाओं को नारेबाजी के बजाय ठोस

योजनाओं में बदलें। यह भी आवश्यक है कि चुनाव आयोग इस दिशा में कोई नीति बनाए ताकि अवैध और अव्यावहारिक वादों से जनता को भ्रमित न किया जा सके। ऐसे में विमर्श का विषय यह है कि क्या हमें यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावी घोषणा-पत्र में किए गए वादे को वास्तविक रूप में पूरी तरह से लागू किया जाए? दरअसल चुनावी घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से उन नीतियों की एक सूची है जो एक राजनीतिक दल के द्वारा चुनाव के समय जनता के समक्ष अपने इरादों, उद्देश्यों या विचारों को चुनावी घोषणा-पत्र के रूप में प्रकाशित करती है। मतदान के बाद यदि वह पार्टी सत्ता में आती है तो उन नीतियों पर काम करेगी, ऐसा इसमें कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से यह चुनाव घोषणा-पत्र एक विजन डॉक्यूमेंट है। इसलिए यह घोषणा-पत्र वैधानिक और कानूनी रूप से लागू करने वाला एक योग्य दस्तावेज बनना चाहिए। निश्चित रूप से चुनावी घोषणा-पत्र मतदाताओं के लिए निर्णय लेते समय राजनीतिक दलों के शासन के एजेंडे को उनके विचारों को मापने का एक सशक्त माध्यम है। यह भी कहा जा सकता है कि मतदान लेन-देन के जैसा है। एक बार जब चुनावी वादों पर वोट दिए जाते हैं तो यकीनन इसे एक कानूनी अनुबंध माना जाना चाहिए। जब कोई पार्टी चुनाव जीत कर सत्ता में आती है तो सवाल उठता है कि क्या वह घोषणा-पत्र जो एक अनुबंध का रूप ले चुका है, उसे लागू होना चाहिए या नहीं? जिस सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के तहत सरकारें चुनी जाती हैं, क्या किए गए वादों को पूरा करने के संदर्भ में उनकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? चुनाव आयोग को भी इस बारे में नए सिरे से विचार करना चाहिए, ताकि इसका कुछ ठोस समाधान किया जा सके। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि घोषणा पत्र लोकतंत्र के महाकुंभ में जनता को प्रभावित करने का सबसे सशक्त माध्यम हैं, परंतु जब तक वे केवल वादों की झड़ी बने रहेंगे और उनके पालन की कोई बाध्यता नहीं होगी, तब तक यह लोकतंत्र की सार्थकता को अधूरा रखेंगे। बिहार के दोनों गठबंधनों के घोषणा पत्र लोकातांत्रिक उत्सव की चमक को बढ़ाते हैं, पर उनका सच समय के साथ ही सामने आएगा कि वे जनता की उम्मीदों को पूरा करते हैं या सिर्फचुनावी छलावे साबित होते हैं।

यह निजी विचार है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप हों चुनावी घोषणाएँ

लेखक: प्रो. (डा.) मनमोहन प्रकाश

लोकतंत्र में चुनाव केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि जनहित और नीति-निर्माण की दिशा तय करने का माध्यम होते हैं। जनता हर बार यह उम्मीद करती है कि जो भी दल सत्ता में आए, वह उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाएगा। परंतु आज के परिदृश्य में चुनावी घोषणाएँ विकास के विजुन से अधिक लोकलुभावन प्रतिस्पर्धा का रूप ले चुकी हैं। राजनीतिक दल एक-दूसरे से आगे बढ़ने के लिए ऐसे वादे करने लगे हैं जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति और संसाधनों की सीमा से बहुत दूर हैं।

हर चुनाव में +मुफ्त बिजली+, +नौस सिलेंडर+, +बेरोजगारी भत्ता+, +लैपटॉप+, +यात्रा सुविधा+ और यहाँ तक कि +नकद राशि+ देने जैसी घोषणाएँ सुनने को मिलती हैं। ये वादे जनता को आकर्षित तो करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्य की अर्थव्यवस्था इतने बोझ को वहन कर सकती है? अधिकांश राज्यों के बजट पहले से ही घाटे में हैं। ऐसे में अव्यवहारिक घोषणाएँ न केवल आर्थिक संतुलन बिगाड़ती हैं, बल्कि आने वाली सरकारों को कर्ज और वित्तीय संकट की ओर धकेल देती हैं।

राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि वादे केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि शासन की जवाबदेही का आधार होते हैं। जब कोई दल असंभव घोषणाएँ करता है, तो वह जनता के विश्वास के साथ-साथ राज्य की वित्तीय साख से भी खिलवाड़ करता है। अतः आवश्यक है कि चुनावी घोषणाएँ प्रदेश की अर्थव्यवस्था, बजट और राजस्व की वास्तविक स्थिति के अनुरूप हों।

इस दिशा में राजनीतिक दल, चुनाव आयोग और वित्तीय संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। चुनाव आयोग को निम्न प्रावधान लागू करने पर विचार करना चाहिए : (अ)प्रत्येक दल अपने घोषणापत्र के साथ आर्थिक व्यौरा प्रस्तुत करे, जिसमें बताया जाए कि वादों की पूर्ति के लिए धन कहाँ से आएगा। (ब)राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक के आर्थिक भार वाले वादों को अस्वीकार्य घोषित किया जाए। (स) राजनैतिक दलों की सहमति से स्वतंत्र आर्थिक समीक्षा समिति गठित की जाए, जो चुनावी घोषणाओं की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करे और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करे। (द)असंभव या भ्रामक वादों पर दंडात्मक प्रावधान हो, ताकि राजनीतिक ईमानदारी बनी रहे। भारत की वित्तीय संस्थाएं तथा अर्थशास्त्री समय-समय पर +फ़्रीबी कल्चर+ को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। सभी का स्पष्ट मत है कि मुफ्त योजनाओं की अंधी दौड़ दीर्घकाल में आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा है। ऐसे में वित्तीय अनुशासन को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ना न केवल आवश्यक, बल्कि लोकतंत्र की सेहत के लिए अनिवार्य हो गया है। यदि राजनीतिक दल वास्तव में जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो उन्हें चाहिए कि वे वादों की संख्या नहीं, गुणवत्ता बढ़ाएं। ऐसी घोषणाएँ करें जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल, पर्यावरण और स्वावलंबन से जुड़ी हों तथा राज्य के विकास केन्द्रित हो। सभी को ध्यान रखना होगा कि मुफ्त की वस्तुएँ नहीं, बल्कि सृजन के अवसर देना ही सच्चा जनकल्याण है। +प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप घोषणाएँ+ केवल एक नीति नहीं, बल्कि एक नैतिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जब चुनावी वादे संसाधनों की वास्तविकता पर आधारित होंगे, तब न केवल शासन विश्वसनीय बनेगा, बल्कि लोकतंत्र भी अधिक परिपक्व होगा। निष्कर्ष रूप में मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में घोषणाएँ आवश्यक हैं, परंतु वे तभी सार्थक हैं जब वे प्रदेश की आर्थिक सीमाओं में रहते हुए जनता के दीर्घकालिक हित को साधें।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन मिशन मीठी क्रांति का आगमन : बेहतर भारत का संकेत

पीआईबी

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी एनबीएचएम एक केंद्र प्रायोजित योजना है।इसे भारत सरकार ने देश में मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देकर गुणवत्ता परक शहद और मधुमक्खी उत्पादन के अन्य उत्पादों को प्रोत्साहित करना था। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित यह योजना आत्मनिर्भर भारत के बैनर पर 500 करोड़ की लागत पर चलाई जा रही है। वर्ष 2020-21 से शुरू इस योजना को पहले तीन साल के लिए लाया गया पर पूरा बजट नहीं खर्चने की वजह से इसकी मियाद तीन साल और बढ़ा दी गयी।

मधुमक्खी पालन एक कृषि जनित गतिविधि है जो आम तौर पर गांवों में किसानों और भूमिहीन श्रमिकों की समन्वित कृषि गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कई पौधों में परागन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जिस्मे फसल उत्पादन और किसानो की आमदनी बढ़ाने में सहायता मिलती है। इस कार्य से कई मूल्य वर्धित मधुमक्खी उत्पाद जिसमे मोम, मधु मक्खी पराग कण, प्रोपोलिस नामक पौधे, रॉयल जेली, बी वेनम इत्यादि के उत्पादन के जरिये किसानों की आजीविका के श्रोत और आमदनी बढ़ती है।

समन्वित खेती और सघन कृषि एक सामान्य और व्यापक शब्द है जिसके जरिया मौजूदा पारम्परिक तरीके की एक फसली खेती के बजाये एक बहुम्सली व समन्वित खेती को अंजाम दिया जाता है। इसका मतलब एक ऐसी कृषि प्रणाली से है जिसमे पशुपालन , मछली उत्पादन, अनाज उत्पादन और बागवानी कृषि सभी समाहित है।

भारत की विभिन्नताओं से भरी कृषि जलवायु परिस्थितियों में मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन और इसके निर्यात की व्यापक क्षमता है। ग्रामीण विकास और सतत कृषि में इसके महत्त्व को समझ कर ही भारत सरकार ने एक नयी मीठी क्रांति अभियान के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय मधुमक्खी शहद मिशन की शुरुआत की। यह एक महत्वाकांक्षी पहल है जिससे देश में गुणवत्तापरक शहद के उत्पादन के साथ किसानों की आमदनी वैज्ञानिक और संगठित तरीके से मधुपालन के जरिये बढे।

राष्ट्रीय मधुमक्खी शहद मिशन की उप योजनाएं
राष्ट्रीय मधुमक्खी शहद मिशन यानी एनबीएचएम का क्रियान्यवन तीन मिनी मिशन एमएम 1 एमएम 2 और एमएम 3



मिनी मिशन 1- इसके अंतर्गत वैज्ञानिक मधु पालन के तहत परागन क्रिया के जरिये विभिन्न फसलों का उत्पादन और उसकी उत्पादकता उन्नयन पर जोर दिया जाता है।

मिनी मिशन 2- यह मिशन मधुमक्खी पालन से जुड़े उत्पादों के आगम के उपरांत के प्रबंधन कार्य मसलन शहद संग्रहण, प्रसंस्करण, भण्डारण, विपणन और मूल्य वर्धन के लिए सभी जरूरी बुनियादी सुविधाओं को मुहैया करता है।

मिनी मिशन 3-यह मिशन देश के सभी क्षेत्रो के कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल तरह तरह के शोध व विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

एनबीएचएम का उद्देश्य एनबीएचएम का मुख्य उद्देश्य है किसानो की आमदनी और रोजगार की बढ़ोत्तरी के लिए मधुमक्खी

पालन उद्योग का संपूर्ण विकास, खेतिहर और गैर खेतिहर परिवारों को आजीविका मुहैया करना और खेती व बागवानी के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।

अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर मधुमक्खियों का एक क्वालिटी न्यूक्लियस स्टॉक बनाना है, फिर इस स्टॉक को कई गुना और बढ़ाकर शहद निकालने के उपरांत की गतिविधियों मसलन शहद प्रसंस्करण प्लांट, भंडारण, शीतायन, संग्रहण, ब्रांडिंग और विपणन की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है।

इसके अलावा शहद उत्पादन वाले जिलों और प्रान्तों में सभी तरह के आधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित करना जिससे सभी शहद उत्पादों की शुद्धता की जांच हो।

तुलसी विवाह एवं छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया



राजनांदगांव। आज तुलसी विवाह एवं छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर सिन्हा परिवार द्वारा विधिविधान से तुलसी विवाह की पूजा-अर्चना की गई। पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार तुलसी माता का श्रृंगार किया गया और भगवान शालिग्राम से उनका विवाह संपन्न कराया गया।

पूजा-अर्चना के पश्चात छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपरा और गौरवशाली इतिहास को याद किया गया। परिवार के सदस्यों ने एक-दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं और प्रदेश की खुशहाली व उन्नति

की कामना की।

इस अवसर पर घरों की सुंदर साज-सज्जा की गई तथा पूरे परिसर को दूधिया रोशनी से नहलाया गया, जिससे वातावरण अत्यंत भव्य और आध्यात्मिक बना रहा। सिन्हा परिवार ने बताया कि तुलसी विवाह और छत्तीसगढ़ दिवस दोनों पर्व एक साथ आने से इस वर्ष का आयोजन विशेष और यादगार बन गया।इस अवसर पर अंगेश्वर सिन्हा ,खुमेशवरी सिन्हा सृष्टि सिन्हा, विवेक सिन्हा, टुकेन्द्र सिंहा, हेमलता सिन्हा,अनुराग सिन्हा,अंजलि सिन्हा, भुनेश्वरी सिन्हा सहित सभी ने देव उठनी पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित किया।

राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम (केरल) में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) में सुगमता पर आठवीं क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया

पीआईबी

नीति आयोग द्वारा 30-31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस), तिरुवनंतपुरम में “‘अनुसंधान और विकास में सुगमता” पर 8वीं क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। परामर्श में भारत के अनुसंधान और विकास इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने और विचार-विमर्श करने के लिए संस्थागत नेताओं, कुलपतियों और वैज्ञानिक मंत्रालय/विभागों का एक प्रतिष्ठित समूह एक साथ आया।

एनसीईएसएस के निदेशक प्रो. एनवी चलपति राव के स्वागत भाषण से सत्र की शुरुआत हुई, जिन्होंने वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए एक अनुकूल वातावरण के महत्व को रेखांकित किया और नवाचार-आधारित विकास को गति देने में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डाला। नीति आयोग के प्रो. विवेक कुमार सिंह ने बैठक के बारे में जानकारी दी और नीति आयोग की अनुसंधान एवं विकास सुगमता पहल के मार्गदर्शक दृष्टिकोण के रूप में आरओपीई प्रेमवर्क - बाधाओं को दूर



करना, सक्षमताओं को बढ़ावा देना ड़्क पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि इस प्रेमवर्क का उद्देश्य शोधकर्ताओं के सामने आने वाली संस्थागत और नीति-स्तरीय चुनौतियों को रेखांकित करना और साथ ही वैज्ञानिक प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु आसान, अंतर-एजेंसी सहयोग और क्षमता विकास जैसे सहायक तकनीकी को बढ़ावा देना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव, डॉ. एम. रविचंद्रन ने अनुसंधान की दक्षता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए

ठोस सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने सेवानिवृत्त वैज्ञानिक प्रतिभा के अनुभव का उपयोग करने, विश्वविद्यालय-उद्योग-सरकार (यूआईजी) इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने, संस्थानों के बीच डेटा साझाकरण को बढ़ावा देना तथा वैज्ञानिक संचार को बेहतर बनाकर अनुसंधान परिणामों को समाज के लिए अधिक प्रासंगिक और समझने योग्य बनाने पर बल दिया। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर डाला कि अनुसंधान एवं विकास में

दो आसान महत्वपूर्ण तत्वों, आंतरिक और बाह्य कारकों पर निर्भर करती है। जहां आंतरिक कारक अनुसंधान संस्थानों की संरचना, प्रशासन और कार्यप्रणाली से संबंधित हैं, वहीं बाह्य कारक नियामक बाधाओं, वित्तपोषण तंत्र और विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय जैसे तत्वों को शामिल करते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अनुसंधान और नवाचार में वैश्विक अग्रणी बनने के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए दोनों आयामों पर एक साथ ध्यान देना जरूरी है।

इस बैठक में केरल के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर भी उपस्थित थे, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि “‘अनुसंधान एवं विकास में सुगमता” नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के व्यापक लक्ष्य से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जन-केंद्रित विकास के साथ जोड़ा जाना चाहिए, और संस्थानों, उद्योगों और सरकारों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण समावेशी विकास की कुंजी है।

भारत अनादि काल से ज्ञान की भूमि रही है : उपराष्ट्रपति

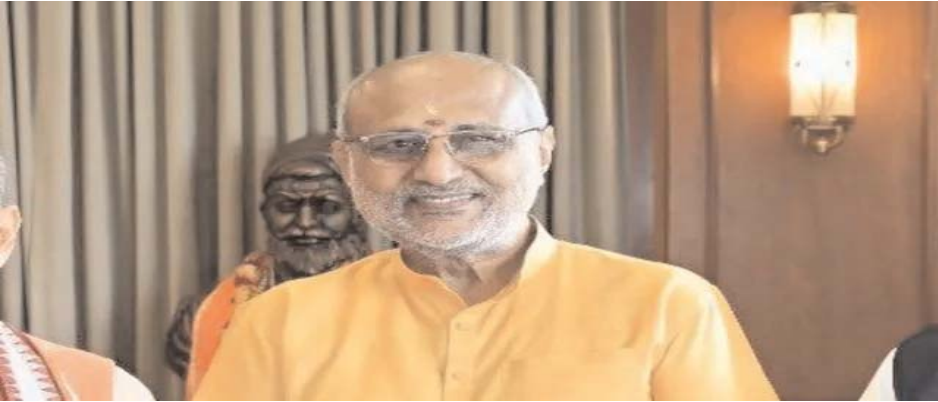
पुस्तकालय भारत के शिक्षा और ज्ञान के शाश्वत सभ्यतागत लोकाचार को प्रतिबिंबित करते हैं : उपराष्ट्रपति

डिजिटल युग में, गलत सूचनाओं के बीच पुस्तकालय विश्वसनीय मार्गदर्शक हैं: उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति ने डिजिटल साक्षरता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने में पुस्तकालयों की भूमिका पर जोर दिया

केरल के 80 वर्षीय पुस्तकालय आंदोलन और पी.एन. पणिक्कर फंडेशन के दृष्टिकोण की प्रशंसा की

पीआईबी। भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने आज एक वीडियो संदेश के माध्यम से तिरुवनंतपुरम के कनकक्कुतु पैलेस में पी.एन. पणिक्कर फंडेशन द्वारा आयोजित +पुस्तकालय समुदायों को सशक्त बनाते हैं - वैश्विक परिप्रेक्ष्य+ विषय पर



अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। यह आयोजन केरल में संगठित पुस्तकालय आंदोलन के 80वें वर्ष का प्रतीक है, जो भारत के पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन के अग्रदूत माने जाने वाले श्री पी.एन. पणिक्कर के विजन से प्रेरित है।

उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में ज्ञान प्रसार के माध्यम से पठन संस्कृति, डिजिटल साक्षरता और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में निरंतर योगदान के लिए पी.एन. पणिक्कर फंडेशन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा

कि फंडेशन का आदर्श वाक्य ड़्क “‘वैचु वलारुका” (पढ़ो और बढ़ो) - समाज को ज्ञान और समावेश की दिशा में लगातार मार्गदर्शन करता रहता है।

श्री सी.पी.राधाकृष्णन ने पुस्तकालयों को शिक्षा के मंदिर के रूप में सराहा और उन्हें ऐसे स्थान के रूप में वर्णित किया जो महत्वपूर्ण सोच का पोषण करते हैं और व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाते हैं।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री आदि शंकराचार्य ने आध्यात्मिक चेतना जागृत करने और विविध विचारों

को एकीकृत करने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि अनगिनत अन्य ऋषियों और विचारकों ने अपने ज्ञान, करुणा और दूरदर्शिता से हमारी सभ्यता को समृद्ध किया है।

भारत की प्राचीन सभ्यतागत प्रकृति पर विचार करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की शिक्षा की परंपरा - महाकाव्यों से लेकर आधुनिक पुस्तकालयों तक - राष्ट्र को ज्ञान और सामाजिक प्रगति की खोज के लिए अग्रसर करती है।

श्री सी.पी.राधाकृष्णन ने इस बात पर भी जोर दिया कि आज के डिजिटल युग में, पुस्तकालय ज्ञान के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं जो लोगों को प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने और गलत सूचनाओं का विरोध करने में सक्षम बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तकनीक सूचना तक आसान पहुंच प्रदान करती है, वहीं पुस्तकालय समाज में गहराई, चिंतन और सार्थक संवाद को बढ़ावा देते हैं।

उपराष्ट्रपति ने शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में केरल की असाधारण विरासत की प्रशंसा की। उन्होंने श्री पी.एन. पणिक्कर को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी दूरदर्शिता ने पुस्तकालयों को जीवंत सामुदायिक केंद्रों में बदल दिया, जिससे पुस्तकें और शिक्षा प्रत्येक नागरिक के करीब पहुंचीं।

ओडिशा के भुवनेश्वर में हथकरघा एवं हस्तशिल्प 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ

विचार-विमर्श में आजीविका को मजबूत करने और विरासत को संरक्षित करने के लिए डिजाइन नवाचार, डिजिटल सशक्तिकरण और सहकारी संघवाद पर जोर दिया गया

पीआईबी

ओडिशा के भुवनेश्वर में आज हथकरघा एवं हस्तशिल्प 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें भारत के हस्तनिर्मित क्षेत्र को विकसित भारत 2047 के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में पुनः परिकल्पित करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालयों द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और क्षेत्र के विशेषज्ञ भारत के हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योगों के विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण तैयार करने हेतु



एक एकरत्र हुए। विचार-विमर्श दो प्रमुख उद्देश्यों पर केंद्रित रहा: हस्तनिर्मित अर्थव्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य का आकलन करना तथा आगामी राष्ट्रीय योजना

की रूपरेखा तैयार करना, जिसका उद्देश्य गहन राज्य भागीदारी, एकीकृत शासन और सतत क्षेत्रीय विकास है। वस्त्र मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम शमी राव ने

आज सम्मेलन के दूसरे दिन की अध्यक्षता की, जिसमें ओडिशा की अपर मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त श्रीमती अनु गर्ग और ओडिशा सरकार की आयुक्त-सह-सचिव (हथकरघा, वस्त्र एवं हस्तशिल्प) श्रीमती पूनम गुप्ता तपस कुमार भी उपस्थित थीं।

अपने संबोधन में, सचिव (वस्त्र) श्रीमती नीलम शमी राव ने उत्पादकता बढ़ाने और कठिन परिश्रम को कम करने के लिए पारंपरिक शिल्प कौशल को आधुनिक उपकरणों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सचिव ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) जैसे संस्थानों से बाजार चक्र से पहले डिजाइन और रंग के रद्धान के पूर्वानुमान में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। अंतर-राष्ट्रीय समन्वय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने हस्तशिल्प क्षेत्र में कुशल आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के बीच कच्चे माल की निर्बाध आवाजाही का आह्वान किया। अपने संबोधन का

समापन करते हुए उन्होंने कहा, हमें उसी इकोसिस्टम की रक्षा करनी चाहिए जिसे हम पोषित कर रहे हैं। चाहे हम इसे हथकरघा कहें या हस्तशिल्प, इसे हमारी अर्थव्यवस्था के एक गौण हिस्से के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए- यह वास्तव में भविष्य का प्रीमियम उत्पाद है। सचिव (वस्त्र) श्रीमती नीलम शमी राव ने यह भी कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच निरंतर संवाद सुनिश्चित करने, सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में परस्पर ज्ञान प्राप्त करने तथा हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए ऐसे सम्मेलन हर छह महीने में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने दोहराया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप एक मजबूत, समावेशी और नवाचार-संचालित हस्तनिर्मित अर्थव्यवस्था के साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए निरंतर समन्वय और आवधिक समीक्षा आवश्यक है। श्रीमती अनु गर्ग ने हथकरघा के सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य को दोहराया तथा कोटपाड़ और डोंगरिया शॉल को टिकाऊ उदाहरण बताया।

शिल्पग्राम में झलकी छत्तीसगढ़ की परंपरा और रचनात्मकता

आगांतुकों को खूब लुभा रही कोसा और रेशमी साड़ियाँ, खादी परिधान

बेलमेटल, काष्ठ कला, माटी कला और टेराकोटा से निर्मित सजावटी वस्तुओं के प्रति दिख रहा झुझान

लोकशक्ति
रायपुर, संवाददाता

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25 वीं वर्षगांठ रजत जयंती के अवसर पर नवा रायपुर में आयोजित भव्य राज्योत्सव में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। राज्योत्सव परिसर में निर्मित शिल्पग्राम में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और विभिन्न स्टॉलों से मनपसंद चीजों की खरीददारी कर रहे हैं। यहां प्रदेशभर से आए बुनकर और शिल्पकार अपने श्रेष्ठ उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय कर रहे हैं, जिनमें कोसा और रेशमी साड़ियाँ, पारंपरिक ड्रेस मटेरियल, खादी परिधान, बेलमेटल, काष्ठ कला, माटी कला और टेराकोटा की आकर्षक वस्तुएँ आगंतुकों को खूब लुभा रही हैं।

शिल्पग्राम प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और शिल्पकला का केंद्र



महोत्सव में स्थापित शिल्पग्राम प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और शिल्पकला का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहां हस्तशिल्प, माटीकला, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रेशम प्रभाग, बिलासा हेंडलूम, हथकरघा इत्यादि के स्टाल लगाए गए हैं। साथ ही राज्योत्सव घूमने

आए लोगों के लिए विशेष सजावट कर रंग-बिरंगे और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आभूषणों, पर्वों के प्रतीकों पर आधारित सेल्फ़े पोइंट भी बनाए गए हैं, जिसमें सेल्फ़े लेने की होड़ मची है।

शिल्पियों को भी बेहतर आय

यहां बिचौलियों के अभाव में

ग्राहकों को उचित मूल्य पर उत्पाद सुलभ हो रही हैं, वहीं शिल्पियों को भी बेहतर आय हो रही है। कुछ दुकानों में अच्छे उत्पाद बाजार से कम मूल्य पर भी उपलब्ध है। ग्राहकों को शिल्पकारों और बुनकरों द्वारा उत्पादों में छूट भी दी जा रही है।



शादी का प्रलोभन देकर अनाचार के आरोपी को किया गिरफ्तार



जांजगीर चांपा / शादी का झांसा देकर अनाचार के आरोपी को अकलतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है । मामले का विवरण इस प्रकार है कि आरोपी से पीड़िता का जान पहचान होने से एक दूसरे को बातचीत करते थे। इसी बीच आरोपी द्वारा पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर कार में घुमाने ले जाने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर पीड़िता के साथ जबरन अनाचार किया, पीड़िता शादी करने के लिए बोली तो आरोपी द्वारा टालमटोल करते हुए मना कर दिया जिसकी सूचना रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 563/2025 धारा 64(2)(रू) ब्रह्म कायम कर विवेचना में लिया गया।

महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए, विजय कुमार पाण्डेय पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी अकलतरा प्रदीप कुमार सोरी के नेतृत्व में आरोपी सीपत बिलासपुर तरफसे पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी अकलतरा,उप निरी.बी.एल कोसरिया,म.प्र.आर स्वाती गिरोलकर, आरक्षक राजा रात्रे का सहायनीय योगदान रहा।

कराते मास्टर ट्रेनिंग सेमिनार का हुआ आयोजन



जांजगीर चांपा / राज्य कराते संघ यूनाइटेड शोतेकान छत्तीसगढ़ एवं जिला कराते संघ जांजगीर चाम्पा के संयुक्त तत्वावधान में 2 नवम्बर रविवार को शिक्षा विभाग डाइट परिसर जांजगीर में कराते मास्टर ट्रेनिंग सेमिनार का आयोजन किया गया । इस अवसर पर कराते संघ के डायरेक्टर वरुण पाण्डेय (ब्लैक बेल्ट 5 डैन) के मार्गदर्शन में प्रि फेड्टिंग, काता, कुमिते, सेल्फ डिफेंस, बेसिक तकनीक, एक्सरसाइज का बहुत ही बारीकी से सम्मिलित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया

गया। इस दौरान प्रदेश सचिव सेंसेई रूखमणी रानू, सेंसेई वीरेंद्र डडसेना महासमुंद,कराते वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष पंकज दास रायपुर,रंगनाथ साहू मालखरीदा,वंशिका चौहान बसना, श्रीजेता बाजपेयी पिथौरा, गीता बरेठ, शालू प्रेमी ,काजल साहू,सना खान, संगीता रात्रे,सीमा सूर्यवंशी, हर्ष तिवारी, निशी धीवर पामगढ़,आराधना खुटे बलौदा, जागृति यादव, सिम्मी यादव बिलासपुर, नेहा यादव, कविता खूटे, वैभवो सिंह अकलतरा,दिनेश चंद्रा, रोशन यादव, मोहरसाय लहरे, विक्रम

सिंह, हितेश बघेल, मनहरण निराला, बिना साहू, परमेश्वर चन्द्रा, अमित सूर्यवंशी, दिलेश्वर रात्रे, चंद्रप्रकाश मौआर, जितेंद्र कुमार सहित अन्य कोच उपस्थित रहे जिन्हें प्रमाण पत्र और ट्रेक शूट प्रदान कर सम्मानित किया गया ।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन आगामी 9 नवम्बर को पूरी ओडिशा में होने वाली ओपन नेशनल कराते चैम्पियनशिप 2025 हेतु किया गया, जो आगामी 8 नवम्बर को पूरी रवाना होगी । उक्ताशय की जानकारी पंकज दास ने दिए ।

संगीतमय श्री राम कथा एवं भव्य संत सम्मेलन का शुभारंभ



रायपुर / श्री दूधाधारी मठ में 2 नवंबर 2025 को संगीतमय श्री राम कथा एवं भव्य संत सम्मेलन का शुभारंभ सुबह 9 बजे हुआ । व्यास पीठ में विराजित होने के लिए श्री अयोध्या धाम से अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी सियाराम शरण दास जी महाराज पधारे हुए हैं। महामंडलेश्वर राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज ने बताया कि यह कार्यक्रम 2 नवंबर से 10 नवंबर 2025 तक आयोजित है। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे एवं अपराह्न 3 से शाम 6 बजे तक निश्चित है। यह कार्यक्रम सत्संग भवन में संचालित हो रहा है। प्रथम दिवस कथा का रसपान करने के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से माधव एक्सप्रेस के संपादक राहुल मिश्रा जी, मठ मंदिर ट्रस्ट कमेटी के सदस्य विजय पाली, राजेश अग्रवाल, विनोद मंगल अग्रवाल, रामकृष्ण पाली, राम छवि दास, शिव शंकर पांडे सहित अनेक गणमान्य नागरिक गण सम्मिलित हुए।

आगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन 17 नवम्बर तक आमंत्रित

जांजगीर-चांपा / एकीकृत बाल विकास परियोजना जांजगीर के जनपद पंचायत नवागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पाली के आंगनबाड़ी केन्द्र 03 में कार्यकर्ता पद रिक्त होने के फलस्वरूप 18 वर्ष से 44 वर्ष के महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किया गया है। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना जांजगीर नवागढ़ ने बताया कि उक्त पद हेतु 12 वीं उत्तीर्ण उक्त ग्राम के किसी भी अग्रणी को आवेदन करना हो तो 17 नवम्बर 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना जांजगीर (जाजवत्येद नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर के पीछे पुराना बाल संरक्षण गृह) में ।

भगत चौक यज्ञस्थल से देवी दाई मंदिर तक निकली भव्य कलश यात्रा



मनमोहक झांकी स्थापना के साथ अखण्ड राम नाम सप्ताह यज्ञ शुरू

रायगढ़ के युवती-महिलाओं द्वारा कर्मा नृत्य ने मोहा बस्तीवासियों का मन



जा रहा है। प्रतिवर्ष वर्ष की भांति इस वर्ष भी 100 साल से अधिक पुराने विशाल वट वृक्ष के नीचे चबूतरे में 64 वें वर्ष में अखण्ड राम नाम सप्ताह यज्ञ का शुभारंभ देव आवाहन, स्थापना पूजा एवं स्वास्ति वाचन व देव मूर्तियों की झांकी स्थापना के साथ हुआ। भगत चौक के आचार्य पं. रामबिलास उपाध्याय, विनोद उपाध्याय (भागवताचार्य) एवं उनके परिवार द्वारा विधि-विधान से पूजा-अर्चना करा राम नाम का जयकारा लगवाते हुए अखण्ड नाम सप्ताह यज्ञ का शुभारंभ करया गया। इसके बाद पूरे भगत चौक के लोगों द्वारा राम नाम का जाप प्रारंभ किया गया। राम नाम का जाप पूरे सात दिन और सात रात लगातार किया जाएगा। साथ ही जिले व अन्य युवाओं में दिख रहा भारी उत्साह वर्षों से चली आ रही परंपरा को कायम रखने के लिए 63 वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखण्ड राम नाम सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष बुजुर्गों से कहीं ज्यादा युवा वर्ग में अखण्ड राम नाम सप्ताह यज्ञ को लेकर उत्साह देखा जा रहा

भी यहां भाग लेने पहुंचेंगी। कलश यात्रा को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति के संस्थापक, संरक्षक, अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, प्रचार प्रसार अध्यक्ष, व्यवस्थापक, मंच संचालन प्रभारी, पुजारी सहित मोहल्लेवासी जुटे हुए हैं।

युवा श्रीराम की भक्ति में सराबोर

वर्षों से चली आ रही परंपरा को कायम रखने के लिए इस वर्ष भी अखण्ड राम नाम सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष बुजुर्गों से कहीं ज्यादा युवा वर्ग में अखण्ड राम नाम सप्ताह यज्ञ को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। युवा टोली इस वर्ष आयोजन शुभारंभ के महीने भर पहले से ही तैयारी में जुटी हुई थी। वहीं कलश यात्रा के दौरान महिला, युवती लाल व पीला साड़ी नें नजर आये वही युवा पीले एवं भगवा रंग के कपड़े में भगवान श्रीराम एवं राधे कृष्ण की भक्ति में सराबोर डूबे दिखे।

लूट करने वाले एक नाबालिक सहित तीन आरोपी चढ़े चाम्पा पुलिस के हत्थे

आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम और एक नग मोबाइल बरामद

जांजगीर चांपा / लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक नाबालिक सहित तीन आरोपी चांपा पुलिस के हथ्थे चढ़ा है जिनके कब्जे से लूट की रकम सहित मोबाइल व बाइक जब्त किया गया है । गिरफ्तार आरोपियों में रितिक सिंह पिता अजय सिंह निवासी भोजपुर , तुषार पिता संतोष बरेठ निवासी शंकर नगर चांपा के साथ एक नाबालिक शामिल है । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सोनू सिदार निवासी मोहंदीखुर्द शक्ति ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह एडवांस कंप्यूटर शक्ति में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम करता है । दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को वह अपने दोस्त लक्षद्वीप के साथ बारात में चापा आया था , दोपहर करीबन 2:30 से 3:00 बजे के बीच नया बस स्टैंड के पास शराब भट्टी में शराब खरीदने गया हुआ था कि उसी समय तीन लड़के एक मोटर साइकिल में आये और मारपीट कर प्रार्थी से 3500 रुपये तथा लक्षद्वीप से 1 नग मोबाइल लूटकर भाग गये । उक्त रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध तत्काल लूट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना जिले के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप, एसडीओपी चांपा यदुमणी सिदार को दिया गया जिस पर अधिकारियों द्वारा तत्काल आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी करने के निर्देश प्राप्त हुए इसके पालन में तत्काल थाना चापा से



निरीक्षक जेपी गुप्ता के नेतृत्व में एक टीम तत्काल मौके की ओर रवाना किया गया। पुलिस टीम के द्वारा घटनास्थल के आस पास लगे सीसीटीवी फुटेज में तीन लड़के एक बाइक में जाते दिखे मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर शंकर नगर तथा भोजपुर क्षेत्र के अलग-अलग स्थान से एक नाबालिक सहित तीन आरोपियों को पकड़ा । पूछताछ करने पर प्रारंभिक तौर पर गुमराह करते रहे परंतु तकनीकी साक्ष्य एवं बारीकी से पूछताछ करने पर आरोपियों ने प्रार्थी एवं उसके दोस्त के साथ मारपीट कर 3500 रुपए एवं 1 नग मोबाइल लूट करने का अपराध घटित करना स्वीकार किया । आरोपी रितिक सिंह के कब्जे से लूट की रकम 1000 रुपए लूट गये 01 नग मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, आरोपी तुषार बरेठ से लूट की रकम 500 रुपए तथा एक नाबालिक से लूट की रकम 500 रुपए इस तरह कुल 2000 रुपये बरामद कर विधिवत कार्यवाही किया गया। उपरोक्त कार्रवाई में निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता थाना प्रभारी चापा, उपनिरीक्षक बेलसज्जर लकड़ा , आरक्षक वीरेश सिंह, शंकर राजपूत, मुदीका दुबे, जय उराव का विशेष योगदान रहा ।

खास खबर

पुलिस स्मृति दिवस पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा में शस्त्र प्रदर्शनी और भाषण प्रतियोगिता आयोजित

कोरबा, पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कोरबा जिले में पुलिस विभाग द्वारा जन-जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा में समाज में पुलिस की भूमिका विषय पर भाषण प्रतियोगिता एवं शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नीतिश ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को पुलिस बल की कार्यप्रणाली, आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा और आधुनिक हथियारों की जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में आर.आई. अनथराम पैकरा, एस.आई. अंगद्व्राज राठौर, उप निरीक्षक अजय सोनवानी (साइबर सेल प्रभारी कोरबा), विकेश्वर प्रताप सिंह, और संजीव सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। निर्णायक मंडल में डॉ. एल. एन. कंवर, डॉ. एस. के. गोभिल, डॉ. दिनेश श्रीवास, प्रो. सुशील गुप्ता और अस्सिस्टेंट प्रोफेसर मधु कंवर शामिल रहे।

अग्निवीर थल सेना भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण का आयोजन 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक

कोरबा जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोरबा द्वारा भारतीय अग्निवीर थल सेना भर्ती 2025 केलिखित परीक्षा में उत्तीर्ण /चयनित अभ्यार्थियों के शारीरिक मापदण्ड परीक्षा हेतु03 नवंबर से 31 दिसंबर तक सी.एस.ई.बी. फुटबॉल ग्राउंड में शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।यह प्रषिक्षण निःशुल्क होगा।प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय कोरबा से संपर्क कर सकते है।

उपभोक्ता आयोग कोरबा में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस

कोरबा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग कार्यालय कोरबा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150 वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को पूर्वाह्न में 10.30 बजे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। जिसमें जिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती रंजना दत्ता द्वारा राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सदस्य पंकज कुमार देवड़ा एवं कर्मचारीगण रामनारायण पटेल, मनीराम श्रीवास, राजेष्वर राव इंले, संजय कुमार शर्मा, नूतन कुमार राजपूत, आरती श्रीवास,दुर्गा चैबे,आनंद ठाकुर उपस्थित थे।

असामर्थिक मृत्यु के दो प्रकरण में आठ लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत कोरबा ।

अपर कलेक्टर कटघोरा द्वारा नदी में डूबने एवं सर्पदंश से मृत्यु कुलदो प्रकरण में पीडित परिवजनों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रुपये के मान से कुल आठ लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

कलेक्टर ने विद्युत गृह विद्यालय में बीएलओ को दिए जा रहे एसआईआर प्रशिक्षण का किया निरीक्षण

बीएलओ को प्रशिक्षण में विशेष ध्यान देने व बारीकियों का गहनता से जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्देश

कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से ना छूटे:- कलेक्टर

कोरबा संवाददाता । भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 के लिए मतदाता सूची के वार्षिक विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियाँ घोषित की गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में विभिन्न प्रपत्रो की प्रिंटिंग एवं प्रशिक्षण कार्य 03 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। ततपश्चात 04 नवंबर से 04 दिसंबर 2025 तक बीएलओ द्वारा डोर टू डोर विजिट कर सर्वेक्षण एवं सूचीकरण कार्य संचालित किया जाएगा। इस हेतु जिले के सभी विधानसभाओं में बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।



इसी कड़ी में कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा कोरबा नगरीय क्षेत्र के विद्युत गृह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 21, कोरबा अंतर्गत नियुक्त बीएलओ के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया। उन्होंने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी बीएलओ को इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से ना छूटे ,तथा

कोई भी अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में ना रहे। सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने बीएलओ को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि एसआईआर कार्यक्रम में बीएलओ की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस हेतु आपसभी प्रशिक्षण में विशेष ध्यान दें, सभी बारीकियों का गहनता से जानकारी प्राप्त कर अपनी शंकाओ एवं सर्वे के दौरान जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं का भी निराकरण प्राप्त कर लें।इस दौरान एसडीएम कोरबा श्री सरोज महिलागे,

मास्टर ट्रेनर श्री गौरव शर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी बीएलओ व बीएलओ सुपरवाइजर को विभिन्न प्रपत्रों , डोर टू डोर सर्वे कार्य, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, स्थानांतरित करने, काटने हेतु उपयोगी प्रपत्रों के बारे में बताया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण में बीएलओ को जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त सर्वे अवधि में बीएलओ प्रत्येक घर के मतदाताओं को गणना पत्रक की दो प्रति बांटेंगे तथा उसको भरने में मतदाताओं को सहयोग भी करेंगे। यदि मतदाता अनुपस्थित हों तो गणना पत्र को घर पर छोड़कर एक सूचना घर के दरवाजे पर चिपकाएंगे जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि बुध लेवल ऑफिसर तीन अलग-अलग तिथियां में गणना पत्रक लेने के लिए पुनः आएंगे। गणना पत्र की एक प्रति बीएलओ अपने पास रखेंगे एवम दूसरी प्रति में मतदाताओं को पावती देंगे। गणना पत्रक पूर्व मुद्रित होगा जिसमें मतदाता की जानकारी मुद्रित होगी। मतदाताओं का वग्रीकरण अलग-अलग श्रेणी में करते हुए

जिसमें सामान्य मतदाता ऐसे मतदाता होंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में भी हो एवं 2003 के गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची में भी हो। इसी प्रकार कुछ मतदाता जिनका नाम 2025 की सूची में तो है, परंतु उनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, परंतु उनके रिश्तेदार जैसे माता या पिता का नाम उस सूची में हो उनका चिन्हांकन करते हुए पत्रक भरा जाएगा । ऐसे दोनों प्रकार के मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल 2003 के मतदाता सूची की स्क्रीनशॉट देनी होगी। जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ होगा एवं उनका नाम 2003 की सूची में नहीं है उन्हें 12 विहित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ हो उन्हें स्वयं के पहचान के लिए 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज तथा माता या पिता में से किसी एक के दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी ।

पेंशन योजनाओं के शेष बचे हितग्राहियों का सत्यापन कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं

कोरबा संवाददाता । आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर अपर आयुक्त श्री विनय मिश्रा ने निगम के समस्त जोन उप प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि वे अपने जोन के अंतर्गत ऐसे शेष बचे सभी पेंशन हितग्राहियों, जिनका सत्यापन अभी तक नहीं किया जा सका है, का वार्षिक सत्यापन शीघ्र पूर्ण कराएं ताकि पेंशन हितग्राहियों को नियमित पेंशन की प्राप्ति में किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित न होने पाएँ। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित केन्द्रीय पेंशन योजनाओं ईंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के पेंशन हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन मोबाईल एप के माध्यम से किए जाने हेतु पूर्व में दिए गए निर्देशों के तहत हितग्राहियों का सत्यापन कार्य निगम



के सभी जोन में आयोजित शिविरों के माध्यम से कराया गया था किन्तु कुछ हितग्राहियों का सत्यापन कार्य किया जाना अभी भी शेष है। शतप्रतिशत हितग्राहियों का सत्यापन कार्य सुनिश्चित किए जाने के मद्देनजर अपर आयुक्त श्री विनय मिश्रा ने समस्त जोन उप प्रभारियों को निर्देश

देते हुए कहा है कि वे अपने क्षेत्रांतर्गत इस हेतु पुनः मुनादी कराएं तथा हितग्राहियों को उनके आधार कार्ड व मोबाईल नम्बर के साथ उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए सत्यापन का कार्य पूरा कराएं ताकि हितग्राहियों को नियमित पेंशन प्राप्ति में किसी प्रकार की समस्या पैदा न हों तथा उन्हें

नियमित रूप से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित हो सके। वहीं हितग्राहियों से भी अपील की गई है कि वे वार्षिक सत्यापन कार्य में सहयोग करें तथा अनिवार्य रूप से अपना सत्यापन करा लें ताकि उन्हें नियमित पेंशन प्राप्त होने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

(कोरबा) । नगर पालिक निगम कोरबा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु गठित आंतरिक शिकायत परिवाद समिति की बैठक निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई, समिति के समक्ष किसी भी प्रकार की शिकायत व परिवाद न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही लंबित है, इस पर समिति के सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा कार्यालय में लैंगिक उत्पीड़न संबंधी विषयों पर सजग रहने व किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित संज्ञान लेने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिरोध और प्रतिरोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगम में आंतरिक शिकायत/परिवाद समिति का गठन किया गया है, जिसकी समय-समय पर बैठक आयोजित की जाती है। इसी कड़ी में निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत में समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक के दौरान पाया गया कि समिति के पास इस संबंध में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और न ही किसी प्रकार का परिवाद लंबित है, इस पर समिति के सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा कार्यालय में लैंगिक उत्पीड़न संबंधी विषयों पर सजग रहने व किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित संज्ञान लेने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में समिति की अध्यक्ष गुलिस्ता साहू, सदस्य सचिव सुभाषिनी आशावान, तारा भगत, कीर्ति अनंत, तिरिथबाई, विनीता सिंह, तुलसीबाई, शिवकुमारी यादव, मालती सोनी, पुष्पा बंजारे, शांतिबाई, रामबाई, तिलका बाई ध्रुव, शीतला गोंड, ललिता टंडन आदि उपस्थित थे।

गौवंश संरक्षण पर अनोखी प्रदर्शनी: श्री तेजकरण जैन के ‘गौवंश संग्रह’ ने सबका मन मोहा

कोरबा गौसेवा एवं गौवंश संरक्षण के प्रति गहरी निष्ठा रखने वाले समाजसेवी श्री तेजकरण जैन द्वारा तैयार गौवंश पर आधारित अनोखा और विशाल संकलन 30 अक्टूबर को अग्रसेन कन्या महाविद्यालय प्रांगण में प्रदर्शित किया गया। इस निःशुल्क प्रदर्शनी में दर्शकों ने विश्व के अनेक देशों के 476 नोट देखे जिन पर गाय की छवि अंकित है। साथ ही, गाय से संबंधित दुर्लभ सिक्कों का संग्रह भी आकर्षण का केंद्र रहा। प्रदर्शनी में गाय के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा को डाक टिकटों के माध्यम से अत्यंत सुंदर और शिक्षाप्रद रूप में प्रस्तुत किया गया। अग्रसेन कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य झा सर की उपस्थिति में आयोजित इस प्रदर्शनी में विद्यालय

के छात्र-छात्राओं ने बड़ी रुचि से देखा और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त की। बच्चों ने इस अद्वितीय संकलन की सराहना करते हुए कहा कि इससे उन्हें गाय के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में नई जानकारी मिली। प्रदर्शनी में अतिथि चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष एवं लायंस क्लब के पूर्व गवर्नर रामसिंह अग्रवाल, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष योगेश जैन, राजेन्द्र तिवारी, पारस जैन, अनिल अग्रवाल और संजय अग्रवाल सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। प्रदर्शनी के सफ़्त आयोजन में महाविद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने ली राष्ट्रीय एकता की शपथ

0 अपर आयुक्त विनय मिश्रा ने साकेत भवन में अधिकारी कर्मचारियों को ग्रहण कराई राष्ट्रीय एकता की शपथ



कोरबा । लौहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर निगम कार्यालय साकेत में नगर पालिक निगम कोरबा के अधिकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली तथा राष्ट्र की एकता, अखण्डता और सुरक्षा को बनाए रखने के संकल्प को दोहराया। निगम के अपर आयुक्त विनय मिश्रा ने अधिकारी कर्मचारियों को शपथ ग्रहण कराई। भारत सरकार द्वारा लौहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने से संबंधित दिए गए दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में नगर

पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। निगम के अपर आयुक्त श्री विनय मिश्रा ने इस मौके पर अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण करते हुए अधिकारी कर्मचारियों ने कहा कि हम सत्यनिष्ठा से शपथ लेते हैं कि हम राष्ट्र की एकता, अखण्डता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करेंगे और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करेंगे। हम यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहे हैं, जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके, हम अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करते हैं। इस अवसर पर उपायुक्त द्वय

बी.पी.त्रिवेदी एवं पवन वर्मा, लेखाधिकारी भवकांत नायक, निगम सचिव रामेश्वर सिंह कंवर, राजस्व अधिकारी अनिरुद्ध सिंह, कार्यालय अधीक्षक अरविंद वानखेड़े, रामसिंह नेताम, अरूण मिश्रा, आनंद दुबे, दिवाकांत जायसवाल, कृष्णा दास महंत, भावेश यादव, पुकराज, लीलाम्बर यादव, द्वारसराम साहू, बीना एथोनी, तारा भगत, दीनदयाल साहू, शंकर साहू, हिमांशु राठौर, सरस्व देवांगन, श्यामलाल साहू, रामकृष्ण सोनी, प्रदीप सिकंदर, रामशंकर पाण्डेय, अरूण वर्मा, परमेश्वर शर्मा, विकास यादव, धनेश यादव, उमाशंकर यादव, शीतला, विकास, बिहारी यादव, प्रमोद, जीवन कर्ष, रविशंकर तिवारी, कमल राठौर, रमेश कुमार सिदार, गरीब दास आदि के साथ अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

जिला पंचायत में खींचतान: सीईओ की कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे सदस्य

कोरबा संवाददाता । जिला पंचायत कोरबा में सदस्यों और जिला सीईओ के बीच खींचतान उभर कर सामने आई है। गुरुवार को सामान्य सभा की बैठक के बाद कलेक्टर के पास पहुंचकर अध्यक्ष सहित सदस्यों ने शिकायत की। हालांकि, अध्यक्ष इससे इनकार कर रहे हैं लेकिन जिला पंचायत सदस्यों ने इस बात की पुष्टि की है। जिला पंचायत सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष पवन सिंह सहित पदेन सचिव व जिला पंचायत सीईओ डीके नाग व विभागों के अधिकारी, जनपदों के अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के सदस्य उपस्थित रहे। कटघोरा डीएफओ कुमार निशांत इस बैठक से नदारद रहे। विभागों की समीक्षा करने के साथ ही विषयों और मांगों पर निर्देश दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी टी.पी. उपाध्याय को उनके अधीनस्थ खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से शिक्षकों का संलग्नीकरण किए जाने पर कार्रवाई के संबंध में हद्दायत दी गई। यह भी पूछ गया कि जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे अवैधानिक संलग्नीकरण से अनजान कैसे हैं? बैठक के दौरान डीएफओ कुमार निशांत की अनुपस्थिति को लेकर सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की। सदस्यों की मानें तो कटघोरा डीएफओ उनका फेन तक नहीं उठाते। अध्यक्ष ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की और चेतावनी दी गई है कि अगली बैठक में डीएफओ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें अन्यथा उनके



विरुद्ध मुख्यमंत्री, वन मंत्री, वन सचिव से शिकायत की जाएगी।

इस बैठक में नहीं आए सीईओ - सामान्य सभा की बैठक के बाद जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें जिला पंचायत सीईओ उपस्थित नहीं हुए। उन्हें बैठक में आने के लिए

बुलाया गया लेकिन वह आना जरूरी नहीं समझे। इसे लेकर अध्यक्ष की नाराजगी सामने आई। सूत्र बताते हैं कि जिला सीईओ के द्वारा जिला पंचायत भवन में स्थित पूर्व सभा कक्ष के दरवाजे पर ताला बंद कर दिया गया है वहीं उन कमरों में भी ताले लगवा दिए गए जहां जिला पंचायत सदस्यों के पति आकर बैठते रहे। जिला पंचायत

प्रशासन का तर्क है कि अनावश्यक उनकी मौजूदगी बनी रहती है इसलिए कमरों में ताला लगवा दिया गया है। इस बात पर जिला पंचायत सदस्यों और अध्यक्ष ने भी पूर्व सभा कक्ष को ताला बंद कराए जाने पर नाराजगी जताई। जिला सीईओ के प्रति नाराजगी और काफी समय से चली आ रही कथित खींचतान को लेकर अध्यक्ष ने

सदस्यों के साथ कलेक्टर के पास पहुंचकर अपनी बात रखी। सूत्र बताते हैं कि जिला सीईओ से इस संबंध में उन्हें तलब कर चर्चा की गई और सदस्यों तथा अध्यक्ष को आश्वासन दिया गया कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। हालांकि, बाहर निकलकर मीडिया से चर्चा में अध्यक्ष इस बात को टाल गए व रुख मोड़ दिया।

हल्ला ब्याज की राशि का

दूसरी तरफ यह बात भी सामने लाई जा रही है- प्रचारित की जा रही है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन काल में जिस तरह से विभिन्न मदों में प्राप्त राशि के ब्याज की रकम जिला सदस्यों और अध्यक्ष को उनके क्षेत्र में कार्यों के लिए दी जाती रही है,उसे मांगा जा रहा है जबकि भाजपा सरकार ने ब्याज की राशि के खर्च पर रोक लगा दी है। प्रचारित किया जा रहा है कि उक्त ब्याज की रकम प्राप्त करने को लेकर सीईओ द्वारा इंकार करने पर यह सारा कुछ घटनाक्रम उभर कर सामने आया है। वैसे बताते चलें कि न सिर्फ जिला पंचायत बल्कि जिले के सभी जनपद पंचायतों में ब्याज ही नहीं बल्कि 15 वित्त वें वित्त की राशि को भी विकास कार्यों की बजाय अनावश्यक कार्यों में खर्च किया जा रहा है। मनमाने तरीके से राशि खर्च की जा रही है और विकास कार्यों को दरकिनार कर दिया गया है। लाखों रुपए उन चीजों पर खर्च किए जा रहे हैं जिनके लिए विभागीय मद आते हैं। ऐसे में इनकी मनमानी चरम पर है जिस पर कोई लगाम नहीं किसी जा रही है।

'दिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया याद

जगदलपुर। राजीव भवन जगदलपुर में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के निर्देशानुसार शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्व.इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की द्वारा दोनों नेताओं के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया व श्रद्धांजलि दी गई।

वरिष्ठ कांग्रेसी उमाशंकर शुक्ला ने भारत रत्न इंदिरा गांधी के शहादत दिवस और लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती को याद कर कहा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया।उन्होंने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत देश के रूप में खड़ा किया।सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने रियासतों का भारत में विलय कराया। उनकी दृढ़ता को देखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी। इस दौरान हनुमान द्विवेदी, अंगद त्रिपाठी, गौरनाथ नाग, पार्षद सूर्यापानी, दिलीप सेठिया, भुवन झा, रविशंकर तिवारी, विजय उडके, वीरेंद्र परिहार, संजय पाणिग्रही, नरेंद्र तिवारी, हरिशंकर सिंह, विक्रांत सिंह, सलीम जाफर अली, खिरेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।



बस्तर और तोकापाल में राजनीतिक दलों के बूथ लेबल अभिकर्ताओं को दिया गया

जगदलपुर। निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025-26 की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सफल, समावेशी और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से बस्तर और चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों को प्रशिक्षण दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बस्तर और तोकापाल द्वारा शनिवार 01 नवंबर को विभिन्न राजनैतिक दलों के बूथ लेबल एजेंटों (क़क़) के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। यह सत्र विधानसभा क्षेत्र

क्रमांक 85-बस्तर (अजजा), 84-नारायणपुर (आंशिक), और 87-चित्रकोट अजजा के समस्त मतदान केंद्रों के लिए नियुक्त बूथ लेबल एजेंटों को उनके दायित्वों और निर्वाचक नामावली को अद्यतन करने की तकनीकी बारीकियों से अवगत कराने के लिए आयोजित किया गया। बस्तर तहसील के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए यह प्रशिक्षण जनपद पंचायत बस्तर के सभागार में दोपहर 12 से 2 बजे तक आयोजित हुआ, जबकि विधानसभा क्षेत्र 87-चित्रकोट के बूथ एजेंटों के लिए जनपद पंचायत तोकापाल के सभागार में दोपहर 1 से 2 बजे तक सत्र रखा गया था। जिसमें सभी प्रमुख राजनैतिक दलों के बूथ लेबल अभिकर्ता शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल : फरसाबहार में खुलेगा सत्यसाई मातृत्व शिशु अस्पताल



रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। अब फरसाबहार क्षेत्र में सत्यसाई मातृत्व शिशु चिकित्सालय एवं अत्याधुनिक बाल हृदय रोग उपचार अस्पताल की स्थापना की जा रही है। यह अस्पताल देश की प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था सत्यसाई ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया जाएगा।

अस्पताल के लिए जिला प्रशासन ने पांच एकड़ भूमि का चिह्नंकन कर लिया है। स्थायी भवन निर्माण पूरा होने तक ट्रस्ट द्वारा फरसाबहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में अस्थायी रूप से अस्पताल का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण पहल की घोषणा फरसाबहार में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प शिविर के दौरान की।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि रायपुर स्थित सत्यसाई अस्पताल पूरे देश में अपने नि:स्वार्थ सेवा कार्यों के लिए जाना जाता है, जहां बच्चों के हृदय रोग का उपचार पूरी तरह नि:शुल्क किया जाता है, यहां तक कि अस्पताल में कैश काउंटर तक नहीं है। अब तक वहां 40 हजार से अधिक बच्चों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस अस्पताल की सेवा भावना से प्रभावित हैं और शीघ्र ही इसका निरीक्षण करने वाले हैं।मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उन्होंने ट्रस्ट से जशपुर जैसे आदिवासी बहुल जिले में स्वास्थ्य सेवा विस्तार का आग्रह किया था, जिसके परिणामस्वरूप ट्रस्ट ने फरसाबहार में अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह अस्पताल जिले के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके शुरू होने से जशपुर सहित ओडिशा और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चों को भी नि:शुल्क और उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दिसंबर 2023 में पदभार ग्रहण करने के बाद से जशपुर जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं कुनकुरी मेडिकल कॉलेज : मुख्यमंत्री के पहले बजट में घोषित, जिले का वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ। प्रथम चरण में 220 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए 732 करोड़ स्वीकृत, 90 पदों की स्वीकृति, चराईडांड में भूमि चिन्हांकित, अस्थायी रूप से राजा देशरक्षण जिला चिकित्सालय से संचालन की प्रक्रिया जारी।

गदेव राम उरांव स्मृति चिकित्सालय, जशपुरनगर : 735 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर, सीटी स्कैन व अल्ट्रासुनिक आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।गिनाबहार मातृ-शिशु अस्पताल (स्ड॥) : गर्भवती माताओं व नवजात शिशुओं के लिए उच्च स्तरीय केंद्र निर्माणाधीन।

बस्तर और तोकापाल में राजनीतिक दलों के बूथ लेबल अभिकर्ताओं को दिया गया विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रशिक्षण

जगदलपुर। निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025-26 की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सफल, समावेशी और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से बस्तर और चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों को प्रशिक्षण दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बस्तर और तोकापाल द्वारा शनिवार 01 नवंबर को विभिन्न राजनैतिक दलों के बूथ लेबल एजेंटों (क़क़) के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। यह सत्र विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 85-बस्तर (अजजा), 84-नारायणपुर (आंशिक), और 87-चित्रकोट अजजा के समस्त मतदान केंद्रों के लिए नियुक्त बूथ लेबल एजेंटों को उनके दायित्वों और निर्वाचक नामावली को अद्यतन करने की तकनीकी बारीकियों से अवगत कराने के लिए आयोजित किया गया। बस्तर तहसील के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए यह प्रशिक्षण जनपद पंचायत बस्तर के सभागार में दोपहर 12 से 2 बजे तक आयोजित हुआ, जबकि विधानसभा क्षेत्र 87-चित्रकोट के बूथ एजेंटों के लिए जनपद पंचायत तोकापाल के सभागार में दोपहर 1 से 2 बजे तक सत्र रखा गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘कॉफी टेबल बुक’ का किया मोचन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ‘कॉफ़ी टेबल बुक’ का किया विमोचन:छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा और ‘मोदी की गारंटी’ का दस्तावेज़

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ‘कोसा कॉफ़ी टेबल बुक’ का विमोचन किया। जनसंपर्क विभाग का यह विशेष प्रकाशन प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में हुए जन-कल्याणकारी कार्यों और विकास यात्रा का विस्तृत दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह कॉफ़ी टेबल बुक प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी के अंतर्गत पूरे हुए विकास कार्यों का प्रमाण है। इसमें उन योजनाओं और पहल का समावेश है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती पर विश्वास, विकास और पारदर्शिता का नया अध्याय लिखा है। ‘कॉफ़ी टेबल बुक’ में प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को मिले आवास, किसानों को दी गई धान बोनस राशि, कृषक उन्नति योजना के तहत हुए कृषि सुधार, तथा लोक सेवा आयोग (क़क़ट्ट) परीक्षा मूल्यांकन



प्रणाली में लायी गई पारदर्शिता जैसे अनेक जनहितकारी सुधारों का विस्तारपूर्वक विवरण शामिल है। ‘कॉफ़ी टेबल बुक’ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं - जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, हर घर जल मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और डिजिटल प्रशासनिक सुधार - के माध्यम से छत्तीसगढ़ में आए सकारात्मक परिवर्तनों को चित्रों और

ऑकड़ों के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है।यह पुस्तक न केवल योजनाओं की जानकारी देती है, बल्कि यह बताती है कि किस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से आम नागरिकों का जीवन बदला है। ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के अवसर, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और प्रशासनिक पारदर्शिता के क्षेत्र में हुए कार्यों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है।

एनआईटी रायपुर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का हुआ समापन

विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दिए गए पुरस्कार

रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित किया गया। एनआईटी रायपुर में 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर विजिलेंस अवेयरनेस वीक का आयोजन संस्थान के मुख्य विजिलेंस अधिकारी डॉ. प्रभात दीवान के मार्गदर्शन में किया गया। इस सप्ताह के अंतर्गत विशेषज्ञ व्याख्यान,निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, नुक्रड़ नाटक तथा पुरस्कार वितरण समारोह जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। समापन समारोह के मुख्य अतिथि एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ.एन.वी. रामना राव रहे, साथ ही कार्यक्रम में फैकल्टी मेंबर्स और प्रतिभागी भी उपस्थित रहे। सबसे पहले डॉ. विवेक अग्निहोत्री ने कार्यक्रम के दौरान हुई विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के बारे में बताया तथा विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की।

डॉ. एन. वी. रामना राव ने अपने संबोधन में कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर होना ईमानदारी और एकता के मूल्यों को सशक्त बनाता है। उन्होंने

सभी से भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक रहते हुए संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने का आह्वान किया। मुख्य सतर्कता अधिकारी डॉ. प्रभात दीवान ने कहा कि सतर्कता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि जीवन का दृष्टिकोण है। उन्होंने विद्यार्थियों को ऐसे आयोजनों से अधिकतम लाभ प्राप्त होने की बात कही और सभी को निष्ठा, पारदर्शिता व सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम की विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर ध्रुव शर्मा, द्वितीय स्थान पर अनुज चंद्र झा और तृतीय स्थान पर सई भाकरे एवं आयुषी तिवारी संयुक्त रूप से विजेता रहे। वाद-विवाद प्रतियोगिता में पक्ष वर्ग से प्रथम स्थान पर जागृति सिंह, द्वितीय स्थान पर आस्था प्रधान रही, वहीं विपक्ष वर्ग में प्रथम स्थान संकल्प वैद्य और द्वितीय स्थान रोहित तुरानी ने प्राप्त किया। इन सभी प्रतिभागियों को समापन समारोह में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के पहले एक नुक्रड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। नाटक के माध्यम से सतर्कता, ईमानदारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता का संदेश दिया गया। इस प्रस्तुति में उदाहरणों के माध्यम से यह दिखाया गया कि भ्रष्टाचार कहीं-कहीं और किस प्रकार हो रहा है और इससे कैसे लड़ा जा सकता है।

अब ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया हुई और अधिक पारदर्शी

0 आधुनिक तकनीक से होगा ड्राइविंग टेस्ट: परिवहन मंत्री केदार कश्यप जगदलपुर, 01 नवंबर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों की योग्यता और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंसिंग प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परिवहन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य के 8 जिले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा में ई-ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (ई-ट्रैक) की स्थापना की जा रही है।

इन आधुनिक ई-ट्रैकों के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी तरीके से लिए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि ड्राइविंग परीक्षण में मानव हस्तक्षेप कम हो, निष्पक्षता बनी रहे और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। ई-ट्रैक प्रणाली में वाहन नियंत्रण, लेन अनुशासन, सिग्नलिंग, गति नियंत्रण और सड़क सुरक्षा से जुड़ी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसमें लगे डिजिटल सेंसर और कैमरे अभ्यर्थियों की ड्राइविंग क्षमता का सटीक मूल्यांकन करेंगे। इससे लाइसेंस प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी तथा पात्र आवेदकों को समय पर सही परिणाम प्राप्त होंगे।

परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यह पहल न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ाएगी बल्कि छत्तीसगढ़ को स्मार्ट परिवहन व्यवस्था की दिशा में आगे ले जाएगी। सुस्थिति और आधुनिक परिवहन व्यवस्था राज्य के लोगों के जीवन में सहजता और भरोसा लाएगी। उन्होंने कहा कि यह राज्य में सुरक्षित, स्मार्ट और विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। परिवहन सचिव एस. प्रकाश ने कहा कि ई-ट्रैक की मदद से योग्य चालकों को प्रमाणित किया जाएगा, जिससे जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा मिलेगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि इन जिलों में ई-ट्रैक शुरू होने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन और अपॉइंटमेंट बुकिंग के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। सफल परीक्षण के बाद उन्हें डिजिटल फ़ीडबैक और लाइसेंस जारी किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और सर्वांगीण विकास की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक संस्कृति के अनुरूप पूजा-अर्चना कर राज्य की धरोहर, संस्कृति, मातृशक्ति और स्वाभिमान की प्रतीक



छत्तीसगढ़ महतारी को नमन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी हमारी अस्मिता, आस्था और गर्व का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह भूमि मातृशक्ति की आराधना वाली भूमि है और छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से ही प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने प्रदेशवासियों को राज्योत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार

आम जनता के जीवनस्तर

में सुधार, महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, युवाओं को रोजगार, आदिवासी समाज की उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रजत जयंती वर्ष प्रदेश के लिए नई ऊर्जा और संकल्प का प्रतीक है। आज का दिन विशेष रूप से गौव का क्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ आगमन है और राज्य स्थापना दिवस पर अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से आने वाले समय में प्रदेश निश्चित ही देश के अग्रणी और समृद्ध राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा।

इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा सहित गणमान्य नागरिक और प्रबुद्धजन उपस्थित थे।